Kamal.Sandesh   kamalsandesh.org   KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-19, अंक-04   16-29 फरवरी, 2024 (पाक्षिक)   ₹20

दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेज़ी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना

'प्राण प्रतिष्ठा'
श्री राम मंदिर

निरस्तीकरण
अनुच्छेद 370

सफल
चंद्र मिशन

श्वेत पत्र

25 करोड़ लोग
गरीबी रेखा से ऊपर आए

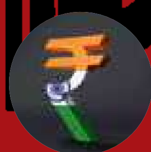

भारत बना
5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

एससी, एसटी, ओबीसी और कमजोर वर्गों के लिए
न्याय

ऐतिहासिक जी20
सफल आयोजन

'मोदी सरकार के शासन में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की'

धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में 03 फरवरी, 2024 को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 26 जनवरी, 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

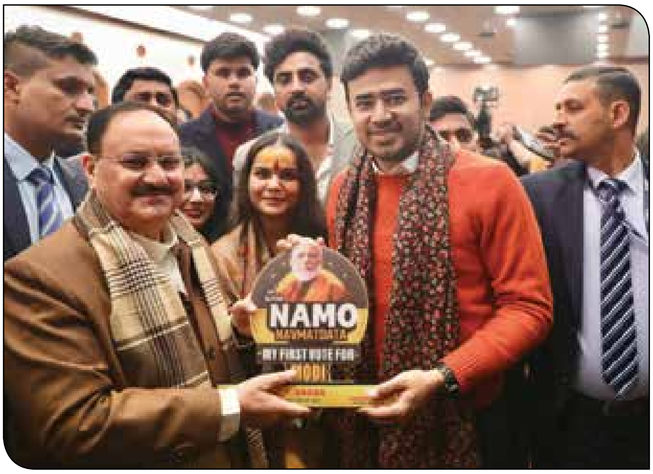

भाजपा मुख्यालय (विस्तार) में 25 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आभासी उपस्थिति में आयोजित 'नमो नवमतदाता सम्मेलन' के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा एवं भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या

नई दिल्ली में 09 फरवरी, 2024 को 'सुशासन महोत्सव 2024' में भाग लेते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा एवं अन्य वरिष्ठ भाजपा नेतागण

नई दिल्ली में 25 जनवरी, 2024 को ब्रेल लिपि में मोदी जी के जीवन और कार्यों पर लिखी गई पुस्तक 'ए प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेन्द्र मोदी– द मेकर ऑफ न्यू इंडिया' का विमोचन करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली में 25 जनवरी, 2024 को प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 के अंतर्गत 'सुपर–100' विजेताओं को सम्मानित करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

बजट सत्र 2024-राष्ट्रपति अभिभाषण

06 यह हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्ष है। इसी कालखंड में आज़ादी के 75 वर्ष का उत्सव, अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतन्त्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया...

11 राष्ट्रपति के अभिभाषण से यह पता चलता है कि भारत किस गति और पैमाने से आगे बढ़ रहा है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर...

14 अंतरिम बजट 2024-25

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र और 'सबका प्रयास' के संपूर्ण राष्ट्र के...

25 पिछले 5 वर्षों का मंत्र 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन': नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महत्वपूर्ण निर्णय लेने और देश को दिशा देने में 17वीं लोकसभा के सभी सदस्यों के प्रयासों की सराहना की...

32 पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को 'भारत रत्न' से सम्मानित किया जाएगा

भारत के पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत के सर्वोच्च नागरिक...

मन की बात

सबकी बातों में राम, सबके हृदय में रामः नरेन्द्र मोदी 31

अन्य

यह बजट 'युवा भारत' की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब हैः नरेन्द्र मोदी 15

यह बजट विकास एवं प्रगति उन्मुख हैः जगत प्रकाश नड्डा 16

भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र 18

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री राम मंदिर अयोध्या धाम प्राण प्रतिष्ठा पर प्रस्ताव पारित किया तथा प्रधानमंत्री को दी हार्दिक बधाई 27

यह हम सभी के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली समय हैः जगत प्रकाश नड्डा 28

22 जनवरी, 2024 दस हजार वर्षों तक ऐतिहासिक दिन रहेगाः अमित शाह 29

संसद का अंतरिम बजट सत्र- एक नजर 30

भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया 33

पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह एवं वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को 'भारत रत्न' दिया गया 34

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

युवा, महिला, गरीब और हमारे अन्नदाता; इन चार स्तंभों के मजबूत होने से देश तेजी से विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगा।

(7 फरवरी, 2024)

जगत प्रकाश नड्डा

पहले देश घोटालों के लिए जाना जाता था, आज सफलताओं के लिए जाना जाता है। हमने Scam से उठकर Success की यात्रा की है। Sports से लेकर Space तक हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

(3 फरवरी, 2024)

अमित शाह

मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया और सहकारिता मंत्रालय बनाकर समृद्ध गांव की नींव डालने का काम किया है।

(30 जनवरी, 2024)

पीयूष गोयल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उपभोक्ताओं को बेहतर कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। 'भारत राइस' का नरेन्द्र मोदी सरकार ने शुभारंभ किया। मैं इस निर्णय के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

(6 फरवरी, 2024)

बी.एल. संतोष

माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को 'भारत रत्न' पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई। सार्वजनिक जीवन में एक संगठक, प्रशासक, संरक्षक के रूप में और मूल्य आधारित राजनीति करने वाले योद्धा को उचित ही सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

(3 फरवरी, 2024)

सुधा यादव

प्रधानमंत्री जन-धन योजना से जन-जन को बैंकिग सेवाओं से जोड़ने का स्वप्न साकार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अब तक 51.04 करोड़ खाते खोले गए और खाताधारकों को एक लाख रुपए तक का बीमा भी प्रदान किया जा रहा है।

(3 फरवरी, 2024)

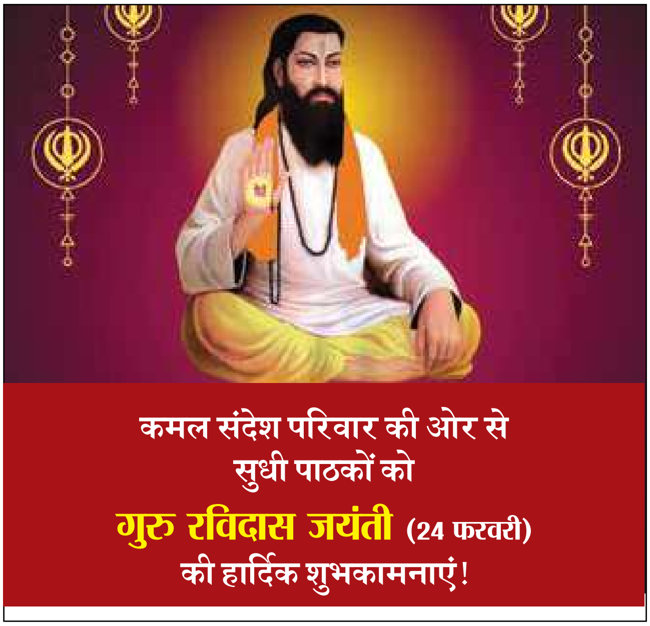

संपादकीय

'फ्रैजाइल-फाइव' से 'टॉप-फाइव'

हाल ही में संपन्न संसद का अंतरिम बजट सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। जहां संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने संबोधित कर देश की अनेक उपलब्धियों को रेखांकित किया, वहीं दोनों सदनों में जिस गंभीरता से सदस्यों ने चर्चा में भागीदारी की उससे जन-जन का विश्वास भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में और भी अधिक मजबूत हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव, अंतरिम बजट, श्वेत पत्र, भगवान श्रीराम मंदिर एवं कई विधेयकों पर हुई चर्चा से पिछले दस वर्षों में देश की अद्भुत उपलब्धियां जन-जन तक पहुंची हैं। जहां चर्चा में अर्थव्यवस्था को संभालकर स्थिर करते हुए विकास की ओर प्रवृत्त किया गया है, वहीं कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के द्वारा छोड़ी गई समस्याओं के समाधान पर भी प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं सुदृढ़ नेतृत्व में 2014 एवं 2019 में मिला भारी जनादेश न केवल कांग्रेसनीत यूपीए काल की आर्थिक कुव्यवस्था एवं वित्तीय कुप्रबंधन से देश को बाहर निकालने का जनादेश था, बल्कि उन चुनौतियों एवं समस्याओं का समाधान कर देश के उज्ज्वल एवं गौरवपूर्ण मार्ग को प्रशस्त करने में मिली जबरदस्त सफलता का जनता द्वारा व्यापक अनुमोदन भी है।

देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर संसद में प्रस्तुत 'श्वेत पत्र' से कांग्रेसनीत यूपीए की दस वर्ष के काल (2004-2014) का वित्तीय कुप्रबंधन, भयंकर भ्रष्टाचार, जनता के धन की खुली लूट एवं कुशासन पूरी तरह से उजागर हुआ है। यह एक स्थापित तथ्य है कि यूपीए का दस वर्ष का कुशासन देश के लिए एक 'खोया हुआ दशक' की रूप में जाना जाता है। साथ ही, श्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व को देश की अर्थव्यवस्था को संकट, निराशा एवं नीतिगत पंगुता के दौर से निकालने का श्रेय जाता है। 'श्वेत पत्र' ने ठीक ही यूपीए काल के शुरुआती एक-दो वर्षों के उच्च विकास दर को अटल बिहारी वाजपेयी-नीत पूर्ववर्ती सरकार के नीतियों का परिणाम बताया है। ध्यान देने योग्य है कि 2004 में श्री अटल जी के नेतृत्व वाली भाजपा गठबंधन सरकार देश को 8 प्रतिशत से अधिक की उच्च विकास दर पर ले गई थी, परंतु इस बढ़त को कांग्रेसनीत यूपीए सरकार आगे नहीं ले जा सकी। इसने राजकोषीय कुप्रबंधन, अत्यधिक एवं अनावश्यक खर्च, आधार एवं जीएसटी जैसी सुधार करने में असफल रहने के कारण अर्थव्यवस्था को संकटपूर्ण स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। देश में भयंकर भ्रष्टाचार, दिशाहीन नीतियां, द्विध्रुवीय शक्ति केंद्र एवं दूरदर्शिता के अभाव के कारण जनता का आत्मविश्वास डोलने लगा तथा देश में भविष्य के प्रति हताशा एवं निराशा का वातावरण निर्मित हुआ। 2014 का भारत विकट परिस्थितियों से जूझ रहा था। अनेक समस्याओं से घिरा देश महंगाई, खाली होता विदेशी मुद्रा भंडार और गिरती विकास दर देश के सामने सुरसा के समान मुंह बाए खड़ी थी। 'श्वेत-पत्र' ने इस काल को ठीक ही 'लॉस्ट डिकेड' (खोया हुआ दशक) की संज्ञा दी है।

भारत की 'फ्रैजाइल-फाइव' से 'टॉप-फाइव' यात्रा को यदि 2014 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो यह एक चमत्कार लगता है। आज भव्य राम मंदिर के निर्माण एवं अनेक सांस्कृतिक केंद्रों के पुनरुद्धार के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, साथ ही देश अपने निःस्वार्थ सेवा के सांस्कृतिक मूल्यों को समर्पित होते हुए पूरी मानवता की सेवा करने के लिए कृतसंकल्पित है

इस चुनौती भरे समय में श्री नरेन्द्र मोदी जनता के लिए एकमात्र आशा की किरण के रूप में उभरे। परिणाम यह हुआ कि 2014 के चुनावों में उनके नेतृत्व में तीन दशकों में पहली बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जब श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तब आर्थिक संकट का समाधान, आर्थिक व्यवस्था को ठीक कर इसकी आधारभूत सुधारों को गति देना उनकी पहली प्राथमिकता थी। 'श्वेत-पत्र' ने इस बात को विस्तृत रूप से रेखांकित किया है कि कैसे कड़ी मेहनत, निरंतर सुधार, भ्रष्टाचारमुक्त शासन तथा गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, किसान, महिला एवं युवा के कल्याण एवं सशक्तीकरण के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। भारत की 'फ्रैजाइल-फाइव' से 'टॉप-फाइव' यात्रा को यदि 2014 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो यह एक चमत्कार लगता है। आज भव्य राम मंदिर के निर्माण एवं अनेक सांस्कृतिक केंद्रों के पुनरुद्धार के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, साथ ही देश अपने निःस्वार्थ सेवा के सांस्कृतिक मूल्यों को समर्पित होते हुए पूरी मानवता की सेवा करने के लिए कृतसंकल्पित है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेज़ी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बनाः द्रौपदी मुर्मु

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 31 जनवरी, 2024 को बजट सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित किया। यह नए संसद भवन में उनका पहला संबोधन था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल की शुरुआत में यह भव्य भवन बना है। यहां 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। श्रीमती मुर्मु ने अपने संबोधन में पीएमएवाई, आयुष्मान भारत, पीएम-किसान आदि जैसी योजनाओं की सफलता का भी उल्लेख किया। उनके संबोधन की मुख्य बातें निम्न हैंः

यह हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्ष है। इसी कालखंड में आज़ादी के 75 वर्ष का उत्सव, अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतन्त्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान—

- मेरी माटी, मेरा देश अभियान के तहत, देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाए गए।
- 2 लाख से ज्यादा शिला-फलकम स्थापित किए गए।
- 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंच प्राण की शपथ ली।
- 70 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर बने।
- 2 करोड़ से ज्यादा पेड़-पौधे लगाए गए।
- दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेज़ी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 क्वार्टर में भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत से ऊपर रही है।
- भारत, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना।
- भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया, धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई।
- ऐतिहासिक G-20 सम्मेलन की सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया।
- भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते।
- पैरा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते।
- भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री-पुल— अटल सेतु मिला।
- भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली।
- भारत, दुनिया में सबसे तेज़ी से 5G रोलआउट करने वाला देश बना।
- भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की।
- पिछले साल भी, मेरी सरकार ने मिशन मोड में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी है।

- 3 दशक बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने के लिए मैं आपकी सराहना करती हूं।

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म

- रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को मेरी सरकार ने लगातार जारी रखा है।
- गुलामी के कालखंड से प्रेरित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास हो गया है। अब दंड को नहीं, अपितु न्याय को प्राथमिकता है। 'न्याय सर्वोपरि' के सिद्धांत पर नई न्याय संहिता देश को मिली है।
- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षित होने वाला है।
- अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा।
- जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से, वहां भी जनजातीय समुदायों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा।
- पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्र-हित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था।
- जम्मू कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने को लेकर शंकाएं थीं। आज वे इतिहास हो चुकी हैं।
- इसी संसद ने तीन तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया।
- इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला कानून बनाया।
- मेरी सरकार ने 'वन रैंक वन पेंशन' को भी लागू किया, जिसका इंतजार चार दशकों से था। OROP लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं।
- भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है।

25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर

- नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं।

बीते 10 वर्षों में:

- हमने भारत को फ्रैजाइल फाइव से निकलकर टॉप फाइव इकॉनॉमीज़ में शामिल होते देखा है।
- भारत का निर्यात करीब 450 बिलियन डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है।
- ITR फाइल करने वालों की संख्या करीब सवा 3 करोड़ से बढ़कर लगभग सवा 8 करोड़ हो चुकी है; यह बढ़ोतरी दो गुना से भी कहीं अधिक है।

एक दशक पहले:

- देश में केवल कुछ सौ स्टार्ट-अप थे जो आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गए हैं।
- दिसंबर 2017 में, 98 लाख लोग GST देते थे, आज इनकी संख्या 1 करोड़ 40 लाख है।
- 2014 से पहले के 10 वर्षों में लगभग 13 करोड़ वाहन बिके थे। पिछले 10 वर्षों में देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे हैं।
- 2014-15 में लगभग 2 हज़ार इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, जबकि 2023-24 में दिसंबर माह तक ही लगभग 12 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं।
- इस दौरान देश को Insolvency and Bankruptcy Code मिला है।

> • देश को GST के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है। • दस वर्षों में कैपेक्स 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही, फिस्कल डेफिसिट भी नियंत्रण में है

फोरेक्स रिज़र्व 600 अरब डॉलर से ज्यादा

- आज हमारे फोरेक्स रिज़र्व 600 अरब डॉलर से ज्यादा हैं।
- हमारा बैंकिंग सिस्टम जो पहले बुरी तरह से चरमराया था, वह आज दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना है।
- बैंकों का NPA जो कभी डबल डिजिट में होता था, वह आज लगभग 4 प्रतिशत ही है।
- भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है।
- भारत का डिफेंस प्रोडक्शन एक लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है।
- आज हर भारतीय देश में बने एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत को देखकर गर्व से भरा हुआ है।
- लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहे हैं।
- उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेन्स कॉरिडोर का विकास हो रहा है।
- Ease of Doing Business में लगातार सुधार हो रहा है।
- बीते कुछ वर्षों में 40 हजार से ज्यादा compliances हटाए या सरल किये गए।
- वन और पर्यावरण विभाग से क्लीयरेंस मिलने में जहां 600 दिन लगते थे, वहीं आज 75 दिन से भी कम समय लगता है।
- हमारे MSME सेक्टर को भी रिफॉर्म्स का बहुत अधिक लाभ हो रहा है।
- आज उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल पर लगभग साढ़े 3 करोड़

MSME रजिस्टर्ड हैं।

- बीते वर्षों में MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत करीब 5 लाख करोड़ रुपए की गारंटी स्वीकृत की गई है। यह 2014 से पहले के दशक से 6 गुना अधिक है।
- मेरी सरकार का एक और बड़ा रिफॉर्म, डिजिटल इंडिया का निर्माण है। डिजिटल इंडिया ने भारत में जीवन और बिजनेस, दोनों को बहुत आसान बना दिया है।
- आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेनदेन का 46 प्रतिशत भारत में होता है।
- दुनिया के दूसरे देश भी आज UPI से ट्रांजेक्शन की सुविधा दे रहे हैं।

डीबीटी से ट्रांसफर हुए 34 लाख करोड़ रुपए

- मेरी सरकार अब तक 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से ट्रांसफर कर चुकी है।
- जनधन आधार मोबाइल (JAM) के कारण करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर किए गए हैं।
- इससे पौने 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं।
- आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत लगभग 53 करोड़ लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बन चुकी है।

आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसका सपना हर भारतीय देखता था। पिछले 10 वर्षों के दौरान:

- गांवों में पौने 4 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनीं हैं।
- नेशनल हाईवे की लंबाई, 90 हजार किलोमीटर से बढ़कर 1 लाख 46 हजार किलोमीटर हुई है।
- एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से दो गुना बढ़कर 149 हो चुकी है।
- देश में 10 हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बिछाई गई है।
- सिर्फ 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है।
- 25 हजार किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए गए। यह कई विकसित देशों के कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई से ज्यादा है।
- इस दौरान भारत में पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरु हुई हैं।
- आज 39 से ज्यादा रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं।
- मेरी सरकार मानती है कि विकसित भारत की भव्य इमारत 4 मज़बूत स्तंभों पर खड़ी होगी।
- ये स्तंभ हैं— युवाशक्ति, नारीशक्ति, किसान और गरीब। देश के हर हिस्से, हर समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही हैं।
- इसलिए इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है।
- 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला। इस पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपये खर्च किये गए।
- लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है।
- हाल में ही 10 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन पूरे हुए हैं।

जनधन आधार मोबाइल (JAM) के कारण करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर किए गए हैं

80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन

- कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब इसे आने वाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब इस पर 11 लाख करोड़ रुपए और खर्च होने का अनुमान है।
- बीते वर्षों में विश्व ने दो बड़े युद्ध देखे और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना किया।
- ऐसे वैश्विक संकटों के बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा, सामान्य भारतीय का बोझ नहीं बढ़ने दिया।
- 2014 से पहले के 10 वर्षों में औसत महंगाई दर 8 प्रतिशत से अधिक थी। पिछले दशक में औसत महंगाई दर 5 प्रतिशत रही।
- पहले भारत में 2 लाख रुपए की आय पर टैक्स लग जाता था। आज भारत में 7 लाख रुपए तक की आय पर भी टैक्स नहीं लगता।
- आयुष्मान योजना के अलावा भी केंद्र सरकार विभिन्न अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। इससे देश के नागरिकों के साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं।
  - जन-औषधि केंद्रों की वजह से मरीजों के करीब 28 हजार करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं।
  - गरीबों को सस्ता राशन मिलता रहे, इसके लिए मेरी सरकार ने पिछले दशक में करीब 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
- जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के तहत, गरीबों को 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की क्लेम राशि मिली है।
- नारीशक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है।
- आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी हैं।
- इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपए बैंक लोन और 40 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।
- मेरी सरकार 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चला रही है।
- नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत, समूहों को 15 हजार ड्रोन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
- मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से देश की लाखों महिलाओं को बहुत मदद मिली है।
- मेरी सरकार ने महिलाओं को पहली बार सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन दिया है।
- आज महिलाएं फाइटर पायलट भी हैं और नौसेना के जहाज को भी

पहली बार कमांड कर रही हैं।

मुद्रा योजना के तहत दिए गए 46 करोड़ से ज्यादा लोन

- मुद्रा योजना के तहत जो 46 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए हैं उनमें करीब 31 करोड़ से ज्यादा लोन महिलाओं को मिले हैं।
- पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2 लाख 80 हज़ार करोड़ रुपए, किसानों को मिल चुके हैं।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30 हज़ार करोड़ रुपए प्रीमियम भरा। इसके बदले उन्हें डेढ़ लाख करोड़ रुपए का क्लेम मिला है।
- पिछले 10 वर्षों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए MSP के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं। यह 2014 से पहले के 10 सालों की तुलना में ढाई गुना अधिक है।
- किसानों को सस्ती खाद मिले, इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं।
- मेरी सरकार ने पौने दो लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। अभी तक लगभग 8 हज़ार किसान उत्पादक संघ - FPO बनाए जा चुके हैं।
- मेरी सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। इसलिए, देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया।
- सहकारी क्षेत्र में, दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है।
- देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है।
- पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए पहली बार मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है।

मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से देश की लाखों महिलाओं को बहुत मदद मिली है

24 हज़ार करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना

- मेरी सरकार ने पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की सुध ली है। उनके लिए लगभग 24 हज़ार करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना बनाई है।
- दिव्यांगजनों के लिए भी मेरी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाया है। साथ ही, भारतीय सांकेतिक भाषा में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराईं हैं।
- हमारे यहां विश्वकर्मा परिवारों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कौशल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी मदद के अभाव में हमारे विश्वकर्मा साथी बुरी स्थिति से गुजर रहे थे। मेरी सरकार ने ऐसे विश्वकर्मा परिवारों की भी सुध ली है। अभी तक पीएम विश्वकर्मा योजना से 84 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं।
- रेहड़ी-ठेले-फुटपाथ पर काम करने वाले साथी भी दशकों से अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। मेरी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना द्वारा उनको बैंकिंग से जोड़ा। इस योजना के तहत, अब तक 10 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार ने इन पर भरोसा करते हुए बिना collateral के ऋण दिया।
- पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की सुविधा दी गई।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- मेरी सरकार ने बाबा साहेब आंबेडकर से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया।
- आज देशभर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए समर्पित 10 संग्रहालय बनाए जा रहे हैं।
- आंतरिक शांति के लिए मेरी सरकार के प्रयासों के सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं।
- जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है।
- नॉर्थ-ईस्ट में अलगाववाद की घटनाओं में भारी कमी आई है।
- नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र घटे हैं और नक्सली हिंसा में भी भारी गिरावट हुई है।
- मेरी सरकार ने 14 सेक्टर्स के लिए PLI योजनाएं शुरु की हैं। इसके तहत अभी तक लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हो चुका है। इससे देश में रोजगार और स्व-रोजगार के लाखों नए अवसर बने हैं।

सोलर पावर कैपेसिटी में 26 गुना बढ़ोतरी

- दस वर्षों में non-fossil fuel पर आधारित ऊर्जा क्षमता 81 गीगावॉट से बढ़कर 188 गीगावॉट हो चुकी है।
- इस दौरान सोलर पावर कैपेसिटी में 26 गुना बढ़ोतरी हुई है।
- बीते 10 वर्षों में 11 नए सोलर पार्क बन चुके हैं। 9 सोलर पार्कों पर आज काम चल रहा है।
- कुछ दिन पहले ही घर की छत पर सोलर एनर्जी उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना घोषित की गई है। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को मदद दी जाएगी। इससे बिजली का बिल भी कम होगा और अतिरिक्त बिजली की खरीद विद्युत बाजार में की जाएगी।
- परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। मेरी सरकार ने 10 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को स्वीकृति दी है।
- मेरी सरकार ने इथेनॉल के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। देश 12 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर चुका है।
- मेरी सरकार ने भारत को दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकॉनॉमीज़ में से एक बनाया है। इससे करोड़ों युवाओं को रोज़गार मिला है।
- मेरी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन पर काम कर रही है। यह भारत के युवाओं को नए अवसर देगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा

पर बल दिया गया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे विषयों की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में प्रारंभ कर दी गई है।

- मेरी सरकार के प्रयासों से देश में ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। उच्च शिक्षा में छात्राओं के दाखिले ज्यादा हो रहे हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के नामांकन में लगभग 44% वृद्धि हुई है। नामांकन में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की 65% और ओबीसी के विद्यार्थियों की 44% से अधिक वृद्धि हुई है।
- इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 10 हज़ार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए है। इनमें 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं।
- साल 2014 तक देश में 7 एम्स और 390 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। वहीं पिछले दशक में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं।
- पर्यटन क्षेत्र युवाओं के लिए रोज़गार देने वाला एक बड़ा सेक्टर है। मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। भारत में घरेलू टूरिस्ट्स की संख्या के साथ ही, भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है।
- मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थों और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। इससे अब भारत में तीर्थ यात्रा आसान हुई है। वहीं दुनिया भी भारत में हैरिटेज टूरिज्म को लेकर आकर्षित हो रही है। बीते एक वर्ष में साढ़े आठ करोड़ लोग काशी गए हैं। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं। उन्नीस लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण, भारत के हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है।

मेरी सरकार ने 14 सेक्टर्स के लिए PLI योजनाएं शुरु की हैं। इसके तहत अभी तक लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हो चुका है। इससे देश में रोजगार और स्व-रोजगार के लाखों नए अवसर बने हैं

- मेरी सरकार भारत को मीटिंग और प्रदर्शनी से जुड़े सेक्टर में भी अग्रणी बनाना चाहती है। इसके लिए भारत मंडपम और यशोभूमि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में टूरिज्म, रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा।
- खिलाड़ियों के साथ ही आज हम स्पोर्ट्स से जुड़े दूसरे क्षेत्रों पर भी बल दे रहे हैं। आज नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन चुकी है। देश में हमने दर्जनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं। इससे स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन के रूप में चुनने का अवसर युवाओं को मिलेगा। खेल उपकरणों से जुड़ी इंडस्ट्री को भी हर प्रकार की मदद दी जा रही है।
- देश के युवाओं में कर्तव्य-बोध और सेवा-भाव का विस्तार करने के लिए 'मेरा युवा भारत' संगठन बनाया गया है। अभी तक इस संगठन से लगभग 1 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं।

भारत विश्व-मित्र के रूप में स्थापित

- संक्रमण काल में एक मजबूत सरकार होने का क्या मतलब होता है, ये हमने देखा है। बीते 3 वर्षों से पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में दरारें पड़ गई हैं। इस कठिन दौर में मेरी सरकार ने भारत को विश्व-मित्र के रूप में स्थापित किया है। विश्व-मित्र की भूमिका के कारण ही आज हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन पाए हैं।
- बीते 10 वर्षों में एक और पुरानी सोच को बदला गया है। पहले डिप्लोमेसी से जुड़े कार्यक्रमों को दिल्ली के गलियारों तक ही सीमित रखा जाता था। मेरी सरकार ने इसमें भी जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत द्वारा G-20 अध्यक्षता के दौरान देखा गया। भारत ने G20 को जिस प्रकार जनता से जोड़ा वैसा पहले कभी नहीं हुआ।
  - पूरी दुनिया ने भारत में हुए ऐतिहासिक -20 सम्मेलन की प्रशंसा की। ऐसे बंटे हुए माहौल में भी एकमत से दिल्ली घोषणापत्र जारी होना ऐतिहासिक है। 'वीमेन लेड डेवलपमेंट' से लेकर पर्यावरण के मुद्दों तक भारत का विजन दिल्ली घोषणापत्र की नींव बना है।
  - हमारे प्रयासों से G20 में अफ्रीकन यूनियन की स्थाई सदस्यता को भी सराहा गया है। इसी सम्मेलन के दौरान भारत-मिडिलईस्ट-यूरोप कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा हुई।
  - मेरी सरकार ने योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की भारतीय परंपराओं को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 135 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग किया।
- सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं जो सदियों का भविष्य तय करते हैं।
- भारत के इतिहास में भी ऐसे अनेक पड़ाव आए हैं।
- इस वर्ष 22 जनवरी को भी देश ऐसे ही एक पड़ाव का साक्षी बना है।
- सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं।
- मेरी सरकार 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने की गारंटी के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नया संसद भवन भारत की ध्येय-यात्रा को निरंतर ऊर्जा देता रहेगा, नई और स्वस्थ परंपराएं बनाएगा।
- वर्ष 2047 को देखने के लिए अनेक साथी तब इस सदन में नहीं होंगे, लेकिन हमारी विरासत ऐसी होनी चाहिए कि तब की पीढ़ी हमें याद करे। ■

राष्ट्रपति के अभिभाषण से यह पता चलता है कि भारत किस गति और पैमाने से आगे बढ़ रहा है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पांच फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। श्री मोदी ने सदन में सेंगोल के उल्लेख से अपने संबोधन की शुरुआत की, जिसने गौरव और सम्मान के साथ उस जुलूस का नेतृत्व किया, जब राष्ट्रपति जी नए संसद भवन में पहुंची और सभी सांसदों ने उनका अनुसरण किया। प्रधानमंत्री ने इस विरासत को रेखांकित किया, जो सदन की गरिमा को कई गुना बढ़ा देती है। उन्होंने कहा कि 75वां गणतंत्र दिवस, नया संसद भवन और सेंगोल का आगमन बहुत महत्वपूर्ण घटना रही। श्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में अपने विचार और सुझाव देने के लिए सदन के सदस्यों को धन्यवाद दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तथ्यों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, जिससे यह पता चलता है कि भारत किस गति और पैमाने से आगे बढ़ रहा है और इस तथ्य के बारे में भी ध्यान आकर्षित करता है कि नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीबों और अन्नदाता के चार स्तंभों से ही देश तेजी से विकसित और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि यह संबोधन इन चार स्तंभों को मजबूत करके देश को विकसित भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

परिवारवाद की राजनीति चिंता का कारण

मजबूत विपक्ष की जरूरत पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र के लिए परिवारवाद की राजनीति चिंता का कारण है। परिवारवादी राजनीति के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राजनीतिक दल जो एक परिवार चलाता है, अपने सदस्यों को प्राथमिकता देता है और जहां सभी निर्णय परिवार के सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, उसे परिवारवादी राजनीति माना जाता है, न कि उस परिवार को जिसके कई सदस्य जनता की सहायता से अपने बल पर राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं।

श्री मोदी ने लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति के खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि मैं राजनीति में उन सभी युवाओं का स्वागत करता हूं जो देश की सेवा करने के लिए यहां आए हैं। उन्होंने लोकतंत्र में परिवारवादी राजनीति के उभरते खतरों के बारे में अफसोस जताया। उन्होंने राजनीति में उभरती इस संस्कृति पर खेद जताया और कहा कि देश में जो विकास हो रहा है वह किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हर नागरिक का है।

भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था

भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की आज दुनिया सराहना कर रही है। इस पर टिप्पणी करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह मोदी की गारंटी है कि मौजूदा सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता से भारत के बारे में विश्व के दृष्टिकोण और उसकी राय से भी यह सार निकाला जा सकता है। देश को समृद्धि की ओर ले जाने में सरकार की भूमिका का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकार द्वारा 2014 में सदन में पेश किए गए अंतरिम बजट और तत्कालीन वित्त मंत्री के बयान के बारे में ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि अपने संबोधन के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आकार के हिसाब से भारत की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बारे में जानकारी दी थी, जबकि आज देश 5वें स्थान पर पहुंच गया है।

तत्कालीन वित्त मंत्री का संदर्भ देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अगले तीन दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने ने कहा कि मैं आज देश को यह आश्वासन देता हूं कि वर्तमान सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

श्री मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व सरकार के कार्य की गति के साथ-साथ उसके बड़े लक्ष्यों और साहस को भी ध्यान से देख

रहा है। उन्होंने सदन को बताया कि वर्तमान सरकार ने ग्रामीण गरीबों के लिए 4 करोड़ और शहरी गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान बनाये हैं। पिछले 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण हुआ है, 17 करोड़ अतिरिक्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए और स्वच्छता कवरेज 40 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत हो गया।

भारतीय नागरिकों की ताकत और क्षमता में विश्वास

जनकल्याण के प्रति पिछली सरकारों के आधे-अधूरे दृष्टिकोण और भारत के लोगों में विश्वास की कमी के बारे में अफसोस जताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय नागरिकों की ताकत और क्षमताओं में वर्तमान सरकार के विश्वास की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पहले कार्यकाल में हम पिछली सरकारों के गड्ढे भरते रहे, दूसरे कार्यकाल में हमने नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत के निर्माण को गति प्रदान करेंगे।

श्री मोदी ने पहले कार्यकाल की सूचीबद्ध योजनाओं— स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुगम्य भारत, डिजिटल इंडिया और जीएसटी का जिक्र किया। इसी तरह उन्होंने बताया कि दूसरे कार्यकाल में देश ने अनुच्छेद 370 का उन्मूलन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने, भारतीय न्याय संहिता को अपनाने, 40,000 से अधिक अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने, वंदे भारत और नमो भारत ट्रेनों की शुरुआत होते देखी है।

> पहले कार्यकाल में हम पिछली सरकारों के गड्ढे भरते रहे, दूसरे कार्यकाल में हमने नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत के निर्माण को गति प्रदान करेंगे

उन्होंने कहा कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक लोगों ने लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा होते देखा है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने सभी को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति सरकार के समर्पण और दृढ़ संकल्प को दिखाया है। राम मंदिर के अभिषेक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर भारत की महान संस्कृति और परंपरा को लगातार ऊर्जा प्रदान करता रहेगा।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा सरकार का तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव रखेगा।

श्री मोदी ने देश के 140 करोड़ नागरिकों की क्षमताओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया कि अगर गरीबों को सही संसाधन और आत्मसम्मान प्रदान किया जाए तो वे गरीबी को हरा सकते हैं। श्री मोदी ने 50 करोड़ गरीबों के पास अपने बैंक खाते, 4 करोड़ के पास अपना मकान, 11 करोड़ के पास पेयजल कनेक्शन, 55 करोड़ के पास आयुष्मान कार्ड और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलने का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि मोदी उन लोगों के लिए चिंतित हैं जिनकी कभी किसी को चिंता नहीं थी। श्री मोदी ने उन रेहड़ी-पटरी वालों का जिक्र किया, जो अब पीएम स्वनिधि के तहत ब्याज मुक्त ऋण लेते हैं। देश में पहली बार कारीगरों और हस्तशिल्पियों के लिए विश्वकर्मा योजना, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पीएम जन मन योजना, वाइब्रेंट सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम कार्यक्रम, मोटे अनाज का उत्पादन, वोकल फॉर लोकल और खादी क्षेत्र को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न

श्री मोदी ने श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और बताया कि कैसे पिछली सरकारों द्वारा इस महान व्यक्तित्व के साथ अनादर का व्यवहार किया गया था। उन्होंने 1970 के दशक में जब श्री ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों का भी स्मरण किया।

हर क्षेत्र में महिलाओं की उल्लेखनीय प्रगति

श्री मोदी ने भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने के बारे में सरकार के योगदान पर प्रकाश डाला। अब भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जहां देश की बेटियों के लिए दरवाजे बंद हों। वे फाइटर जैट उड़ा रही हैं और सीमाओं को भी सुरक्षित रख रही हैं। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों की क्षमताओं पर विश्वास व्यक्त किया, जिनके 10 करोड़ से अधिक सदस्य हैं और जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं।

श्री मोदी ने बताया कि आने वाले वर्षों में देश में तीन करोड़ लखपति दीदियां होंगी। उन्होंने उस सोच में बदलाव पर प्रसन्नता व्यक्त की जहां लड़कियों के जन्म पर भी जश्न मनाया जाता है। श्री मोदी ने महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी विस्तार से बताया।

किसान कल्याण

किसान कल्याण के बारे में जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि वार्षिक कृषि बजट पिछली सरकारों के दौरान 25,000 करोड़ रुपये था, अब बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को

2,80,000 करोड़ रुपये, पीएम फसल बीमा योजना के तहत 30,000 रुपये के प्रीमियम पर 1,50,000 करोड़ रुपये, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए एक समर्पित मंत्रालय का गठन, मछुआरों और और पशुपालक के लिए पीएम किसान क्रेडिट कार्ड देने और जानवरों की जान बचाने के लिए खुरपका और मुंहपका रोग के लिए 50 करोड़ टीकाकरण का भी उल्लेख किया।

युवाओं के लिए सृजित हुए अवसर

भारत के युवाओं के लिए सृजित हुए अवसरों के बारे में प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने स्टार्टअप युग के आगमन, यूनिकॉर्न, डिजिटल सृजकों के उद्भव और उपहार अर्थव्यवस्था के बारे में बात की। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्था है और यह भारत के युवाओं के लिए अनेक नए अवसर पैदा करेगी।

उन्होंने भारत में मोबाइल विनिर्माण और सस्ते डेटा की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दी। श्री मोदी ने भारत के पर्यटन और विमानन क्षेत्र में हुई प्रगति को भी स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं को रोजगार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।

श्री मोदी ने सदन को बताया कि देश का बुनियादी ढांचा बजट जो 2014 से पहले के 10 सालों में 12 लाख करोड़ था, अब पिछले 10 साल में बढ़कर 44 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने उचित प्रणाली और आर्थिक नीतियां विकसित करके देश को विश्व का अनुसंधान और नवाचार केंद्र बनाने के लिए भारत के युवाओं को प्रोत्साहित करने का भी जिक्र किया। देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को हरित हाइड्रोजन और सेमीकंडेक्टर क्षेत्रों में शीर्ष निवेश का उल्लेख किया।

श्री मोदी ने मूल्य वृद्धि पर भी बात की और 1974 में 30 प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर को भी स्मरण किया। उन्होंने देश में दो युद्धों और कोरोनो वायरस महामारी प्रकोप के बीच देश में मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए मौजूदा सरकार की प्रशंसा की। श्री मोदी ने उस समय को याद किया जब सदन की चर्चा देश में घोटालों के इर्द-गिर्द ही घूमती थी। उन्होंने पिछली सरकारों की तुलना में पीएमएलए के तहत मामलों में दोगुनी वृद्धि और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्ती राशि 5,000 करोड़ रुपये से बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये होने का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक के वितरण की जानकारी देते हुए कहा कि सभी जब्त किए गए धन का उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए किया गया।

भ्रष्टाचार से अंत तक लड़ने की प्रतिज्ञा

प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार से अंत तक लड़ने की प्रतिज्ञा की और कहा कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें उसका वापस भुगतान करना होगा। देश में शांति और अमन-चैन बनाए रखने के सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने बताया कि दुनिया आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करने के लिए बाध्य है। उन्होंने अलगाववाद की विचारधारा की निंदा करते हुए भारत के रक्षा बलों की क्षमताओं पर गर्व और विश्वास व्यक्त करते हुए जम्मू-कश्मीर में हो रहे विकास की भी सराहना की।

श्री मोदी ने सदन के सदस्यों से देश के विकास के लिए एकजुट होकर आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने अंत में कहा कि मैं मां भारती और इसके 140 करोड़ नागरिकों के विकास में आपका सहयोग चाहता हूं। ■

राज्यसभा

भारत विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था में शामिल: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का सात फरवरी को जवाब दिया। उनके उत्तर की मुख्य बातें निम्न हैं:

- राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भारत के बढ़ते आत्मविश्वास, आशाजनक भविष्य और लोगों की अपार संभावनाओं पर बल
- भारत फ्रैजाइल फाइव और पॉलिसी पैरालिसिस के दिनों से निकलकर शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल
- पिछले 10 साल सरकार के ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाएंगे
- 'सबका साथ, सबका विकास' कोई नारा नहीं, मोदी की गारंटी है
- मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा
- चार सबसे महत्वपूर्ण जातियों नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और अन्नदाता के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में जानकारी देते हुए श्री मोदी ने दोहराया कि भारत के इन चार प्रमुख स्तंभों के विकास और प्रगति से देश विकसित होगा
- प्रधानमंत्री ने एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के अधिकारों और विकास की भी बात की और कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से यह सुनिश्चित हुआ कि इन समुदायों को जम्मू और कश्मीर में देश के बाकी हिस्सों के समान अधिकार मिले
- श्री मोदी ने विकसित भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि 2047 तक भारत अपने स्वर्णिम काल का फिर से अनुभव करेगा

अंतरिम बजट 2024-25

'यह बजट विकसित भारत के सभी स्तंभों– युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाएगा'

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र और 'सबका प्रयास' के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में एक फरवरी को अंतरिम बजट 2024-25 प्रस्तुत किया। इस बजट की मुख्य बातें निम्न हैं:

भाग – क

सामाजिक न्याय

- चार प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता (किसान) को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस।

'गरीब कल्याण, देश का कल्याण'

- पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की।
- पीएम-जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई।
- पीएम-स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता। 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ।
- पीएम-जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के विकास पर जोर।
- पीएम-विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड-टू-एंड मदद।

'अन्नदाता' का कल्याण

- पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- पीएम-फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई।
- इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट (ई-नाम) के तहत 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद-फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध।

नारी शक्ति पर जोर

- 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए।
- उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत तक बढ़ा।
- स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 43 प्रतिशत नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है।
- पीएम-आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण)

- कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा।
- अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा।
- छत पर सौर प्रणाली लगाना (रूफटॉप सोलराइजेशन) और निःशुल्क बिजली।
- छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300

अंतरिम बजट 2024 पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी

यह बजट 'युवा भारत' की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक फरवरी को पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए इसे केवल एक अंतरिम बजट नहीं, बल्कि एक समावेशी और प्रगतिशील बजट बताया। श्री मोदी ने कहा, "यह बजट निरंतरता का विश्वास लिए हुए है।" प्रधानमंत्री ने कहा, "यह बजट विकसित भारत के सभी स्तंभों— युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाएगा।''

श्री मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा, "निर्मला जी का बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है।" उन्होंने कहा, "यह बजट 2047 तक विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी देता है।"

श्री मोदी ने टिप्पणी की, "यह बजट युवा भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।" उन्होंने बजट में लिए गए दो महत्वपूर्ण फैसलों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के फंड की घोषणा की गई है।" इसके अतिरिक्त, उन्होंने बजट में स्टार्टअप्स के लिए कर छूट बढ़ाने पर भी प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए इस बजट में कुल खर्च में 11,11,111 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि यह भारत में 21वीं सदी के आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेगा। श्री मोदी ने वंदे भारत ट्रेन के मानक की 40,000 आधुनिक बोगियों का निर्माण करने और उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में स्थापित करने की घोषणा के बारे में भी बताया, जिससे देश के विभिन्न रेल मार्गों पर करोड़ों यात्रियों की सुविधा और यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी।

महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "हम एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसे हासिल करते हैं और फिर अपने लिए उससे भी बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं।" उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण और लक्ष्य बढ़ाकर 2 करोड़ और घर बनाने की जानकारी दी। महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारा लक्ष्य महिलाओं को 2 करोड़ 'लखपति' बनाने का था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ 'लखपति' बनाने का कर दिया गया है।"

श्री मोदी ने गरीबों को महत्वपूर्ण सहायता देने, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को इसका लाभ देने के लिए आयुष्मान भारत योजना की प्रशंसा की। उन्होंने रूफ टॉप सोलर अभियान का उल्लेख किया, जहां 1 करोड़ परिवार मुफ्त बिजली का लाभ उठाएंगे, साथ ही सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर प्रति वर्ष 15,000 रुपये से 18,000 रुपये की आय भी अर्जित करेंगे।

प्रधानमंत्री ने आज घोषित आयकर छूट योजना का उल्लेख किया जिससे मध्यम वर्ग के लगभग 1 करोड़ नागरिकों को राहत मिलेगी। किसान कल्याण के लिए बजट में लिए गए प्रमुख फैसलों के बारे में श्री मोदी ने नैनो डीएपी के उपयोग, पशुओं के लिए नई योजना, पीएम मत्स्य सम्पदा योजना के विस्तार और आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान का उल्लेख किया, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होंगे। ■

यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे।

- हरेक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने का अनुमान।

आयुष्मान भारत

- आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण

- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिली है।
- आर्थिक उन्नति रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार।
- 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

बुनियादी ढांचा

- बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत

'अंतरिम बजट 2024' पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य

यह बजट विकास एवं प्रगति उन्मुख है: जगत प्रकाश नड्डा

अंतरिम बजट 2024-25 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट गरीबों के कल्याण पर केंद्रित है और विकास एवं प्रगति उन्मुख है। इस बजट में 'राम राज्य' की परिकल्पना है और इसमें महिलाओं एवं गरीबों की चिंता की गई है। इसमें विकसित भारत की प्रतिबद्धता भी है और यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की बात करता है।

इस बजट में गरीबों के कल्याण, किसानों के उत्थान, महिलाओं के सम्मान और युवाओं की खुशी के लिए प्रतिबद्धता भी है। मैं करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को इतना प्रगतिशील बजट देने के लिए धन्यवाद और बधाई देता हूं जो हमारे देश के सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान की अवधारणा पर अधारित है।

पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 25 लाख से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए कड़ी मेहनत की है, जबकि उनके शासन में हमारी अर्थव्यवस्था ने विकास के नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। यह बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव भी रखता है।

हम 'गरीबी हटाओ' का नारा नहीं देते बल्कि अपनी कड़ी मेहनत एवं नीतिगत पहल से गरीबी मिटाते हैं।

अंतरिम बजट में किसानों और ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं एवं हमारे विशाल मध्यम वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं और इच्छाओं को ध्यान में रखा गया है, यह हमारी अर्थव्यवस्था को विकास के सही मार्ग पर प्रशस्त करेगा और हमें एक उज्ज्वल एवं समृद्ध भविष्य देने का वादा करता है। ■

व्यय के परिव्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगी।

रेलवे

- लॉजिस्टिक्स कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है।
- ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा
- पत्तन संपर्कता गलियारा
- अधिक यातायात वाले गलियारा
- 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को 'वंदे भारत' मानकों के अनुरूप बदला जाएगा।

विमानन क्षेत्र

- देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 पर हुई दोगुनी।
- 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं।
- देश की विमानन कंपनियों ने 1,000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए।

हरित ऊर्जा

- वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी।

पर्यटन क्षेत्र

- राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- पर्यटन केन्द्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा।
- इस प्रकार की गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा।

निवेश

- वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई का अंतर्प्रवाह 596 अरब डॉलर रहा, जो वर्ष 2005 से 2014 के दौरान हुए एफडीआई अंतर्प्रवाह के मुकाबले दोगुना है।
- राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव।

संशोधित अनुमान (आरई) 2023-24

- उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपए है जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ रुपए है।
- कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपए है।
- 30.03 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर और इसके औपचारीकरण को दर्शाता है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 5.8 प्रतिशत है।

बजट अनुमान 2024-25

- उधारी से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
- राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी।
- वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- वर्ष 2024-25 के दौरान डेटेड सिक्योरिटीज़ के जरिए सकल एवं शुद्ध बाजार उधारी क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान।

भाग - ख

प्रत्यक्ष कर

- वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया।
- पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी।
- सरकार करदाता सेवाओं में लाएगी सुधार।
- वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा।
- वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा।
- इससे एक करोड़ करदाताओं को होगा लाभ।

अप्रत्यक्ष कर

- वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बकरार रखने का प्रस्ताव किया।
- जीएसटी ने देश में पूरी तरह बिखरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया।
- इस साल औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपये हुआ।
- जीएसटी कर आधार दोगुना हुआ।
- राज्यों का राज्य जीएसटी राजस्व वृद्धि अनुपात (राज्यों को दी गई क्षतिपूर्ति सहित) जीएसटी से पहले की अवधि (2012-13 से 2015-16) के 0.72 से बढ़कर जीएसटी लागू होने के बाद की अवधि (2017-18 से 2022-23) के दौरान 1.22 हो गया।
- लॉजिस्टिक लागत और करों में कमी से वस्तु और सेवाओं के मूल्य घटने से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा।

पिछले वर्षों के दौरान कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने के प्रयास

- वित्त वर्ष 2013-14 में जहां 2.2 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त थी, वहीं अब सात लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देनदारी नहीं।
- खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया।
- वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की गई।
- विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर कर दर 15 प्रतिशत रखी गई।

करदाता सेवाओं की उपलब्धियां

- कर रिटर्न प्रोसेस करने की औसत समय-सीमा 2013-14 के 93 दिन से घटकर दस दिन रह गई।
- बेहतर दक्षता के लिए चेहरा रहित आकलन और अपील की शुरुआत की गई।
- रिटर्न दाखिल करने के काम को सरल बनाने के लिए नया 26 एएस फार्म और पहले से भरे गये टैक्स रिटर्न विवरण के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अद्यतन किया गया।
- सीमा शुल्क सुधारों से आयतित माल छोड़ने के समय में आई कमी।
- अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में यह 47 प्रतिशत घटकर 71 घंटे रह गया।
- समुद्री बंदरगाहों पर 27 प्रतिशत घटकर 85 घंटे रह गया।

अर्थव्यवस्था— तब और अब

वर्ष 2014 में अर्थव्यवस्था में सुधार और प्रशासन प्रणाली को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी थी। तब समय की जरूरत थी:

- निवेश आकर्षित करना
- बहुप्रतीक्षित सुधारों के लिए समर्थन जुटाना
- लोगों में उम्मीद जगाना
- सरकार 'राष्ट्र प्रथम' की मजबूत भावना के साथ सफल रही ■

भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र

देश पांच कमजोर अर्थव्यवस्था से निकलकर शीर्ष पांच अर्थव्यवस्था में हुआ शामिल

भाजपानीत राजग सरकार ने 2014 में जब केंद्र में सत्ता संभाली, तब देश की अर्थव्यवस्था बेहद नाजुक दौर से गुजर रही थी तथा भारत विश्व की पांच कमजोर अर्थव्यवस्था में गिना जाता था। सार्वजनिक वित्त व्यवस्था चरमरा गयी थी तथा चारों ओर आर्थिक कुप्रबंधन, वित्तीय अनियमितता और व्यापक भ्रष्टाचार का बोलबाला था। यह संप्रग सरकार द्वारा विरासत के रूप में छोड़ी गई अत्यंत विकट स्थिति थी। फिर भी भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने विरासत में मिली हर चुनौती का बेहतर आर्थिक प्रबंधन और सुशासन के जरिए डटकर मुकाबला किया, जिसके परिणामस्वरूप अब देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर उच्च विकास के मार्ग पर अग्रसर है। यह उचित नीतियों, सच्चे इरादों और सही निर्णयों से संभव हुआ। केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संप्रग सरकार (2004-2014) के आर्थिक कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार तथा राजग सरकार (2014 से अब तक) की बेहतर आर्थिक नीतियों, सुधारों एवं इसके प्रभाव पर प्रकाश डालने के लिए संसद में आठ फरवरी को एक श्वेत पत्र पेश किया। यह 'श्वेत पत्र' 2014 से पहले और बाद में देश के आर्थिक व राजकोषीय प्रबंधन तथा प्रशासन की प्रकृति के बारे में स्पष्ट प्रकाश डालता है तथा यह भी बताता है कि कैसे भाजपानीत राजग सरकार ने अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और 'अमृत काल' में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के अनेक प्रयास किये हैं। इस 'श्वेत पत्र' की मुख्य बातें निम्न हैं:

विरासत में **8% की विकास दर की एक मजबूत अर्थव्यवस्था** मिलने के बावजूद, संप्रग सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन तथा व्यापक भ्रष्टाचार के कारण भारत को **'कमजोर-पांच अर्थव्यवस्था'** (फ्रैजाइल-फाइव) में गिना जाने लगा।

- बैंकिंग क्षेत्र पूरी तरह चरमरा गया, जिसके कारण मार्च, 2004 में **6.6 लाख करोड़ रुपए** से मार्च, 2012 तक **39 लाख करोड़ रुपए** तक ऋणों में तीव्र वृद्धि देखी गई। इसके अतिरिक्त, **लगातार उच्च राजकोषीय घाटा**, जो लगातार छह वर्षों (वित्तीय वर्ष 2009-2014) तक **सकल घरेलू उत्पाद के 4.5%** से ऊपर रहा, ने समग्र आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। बाजार के उधार पर सरकार की निर्भरता ने पूंजीगत व्यय में बाधा उत्पन्न की तथा कुल व्यय के रूप में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी **वित्त वर्ष 2004 में 31% से घटकर वित्त वर्ष 2014 में 16%** तक हो गई।
- जुलाई, 2011 में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 294 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर अगस्त, 2013 में लगभग 256 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो सितंबर, 2013 तक मुश्किल से 6 महीने के आयात को कवर कर सकता था।
- यूपीए सरकार ने मुख्यतः राजनीतिक उद्देश्यों के लिए **अत्यधिक राजस्व व्यय को उचित ठहराने के लिए वैश्विक वित्तीय संकट का फायदा उठाया** था।
- यूपीए सरकार द्वारा लगाए गए सख्त तटीय नियमों ने 83 तटीय जिलों में **आर्थिक वृद्धि और विकास को अवरुद्ध** कर दिया। इसके अतिरिक्त, मुख्य घोटाले– जैसेकि **2जी स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला आवंटन घोटालों** के कारण भारत में गंभीर राजनीतिक अनिश्चितता का वातावरण बना और वैश्विक रूप से निवेश स्थल के रूप में भारत की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- **यूपीए सरकार** ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने में **कई अड़चने पैदा की**, जिसकी वजह से उसे आलोचना का सामना करना पड़ा और एकीकृत बाजार की पहल बाधित हुई। इसके अतिरिक्त, 2006 में पेश किया गया 'आधार' एक से दूसरे मंत्रालयों के बीच मतभेदों से जूझ रहा था और इसमें एक समान उद्देश्य का अभाव था, जो अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा।
- **यूपीए** के कार्यकाल वाले दशक को एक **विफल दशक** माना जाता है, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मजबूत बुनियादी अर्थव्यवस्था और वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों को आगे बढ़ाने का अवसर गंवा दिया।
- यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान **अकुशल नीति नियोजन** के कारण 2004 से 2014 तक 14 प्रमुख सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र के मंत्रालयों में 94,060 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए। इसके विपरीत, मोदी सरकार के अंतर्गत 2014 से 2024 तक केवल 37,064 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए, जो कि संचयी बजट अनुमान का 1% से भी कम था।
- **यूपीए सरकार के अंतर्गत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था**, जिसमें **कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2जी घोटाला** और **एंट्रिक्स-देवास डील से**

लेकर शारदा चिट फंड घोटाला तक शामिल था। विकास को प्राथमिकता देने की बजाय यूपीए सरकार ने **हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार** किया और कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा।

- मोदी सरकार के कार्यकाल में **खुले में शौच को खत्म करने**, पूरी योग्य आबादी को स्वदेशी टीकों के साथ सफलतापूर्वक **टीकाकरण** करने और **डिजिटल क्रांति का नेतृत्व** करने जैसी उपलब्धियां शामिल हैं। **यूपीए सरकार की अक्षमताओं** और **अकुशल नीतियों** की वजह से **भारत पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल** हो गया।
- मोदी सरकार के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण ने केवल एक दशक में **भारत को शीर्ष पांच देशों की श्रेणी** में लाकर खड़ा कर दिया है, और अब **वर्ष 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** बनने की राह पर अग्रसर है।
- व्यापक अर्थव्यवस्था में यूपीए का कुप्रबंधन **नकारात्मक चालू खाता शेष से स्पष्ट हो जाता है,** जहां वर्ष 2013-14 में सकल **घरेलू उत्पाद की दर -4.8%** थी और साल-दर-साल सकल घरेलू उत्पाद **5.5 प्रतिशत की धीमी रफ्तार से ही चल रही थी**। जबकि इसकी तुलना में **मोदी सरकार के कार्यकाल के वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत हो गई थी।**
- मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान **पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 24 में 28% हो गया है जो कांग्रेस की सरकार के दौरान वर्ष 2014 के वित्त वर्ष में केवल 16 प्रतिशत था**। यही नहीं, **यूपीए की लापरवाही** के कारण वित्त वर्ष **2015 में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण केवल 12 किलोमीटर प्रतिदिन** था, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल मे **यह वित्तीय वर्ष 2023 में 2.3 गुना से अधिक बढ़कर 28 किमी/दिन हो गया था**। इसके अतिरिक्त, **प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात भी 581 मीट्रिक टन से बढ़कर 784 मीट्रिक टन** हो गया। इसके साथ ही, **वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2022 तक विद्युतीकृत रेल मार्ग और हवाई अड्डों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई थी।**
- मोदी सरकार ने **'सबका साथ, सबका विकास'** के दर्शन को सही मायने में अपनाया है:
  - ❑ **यूपीए सरकार ने वर्ष 2011-2014 तक केवल 1.8 करोड़ शौचालयों** का निर्माण किया, वहीं **मोदी सरकार ने वर्ष 2014-2024 तक उल्लेखनीय 11.5 करोड़ घरेलू शौचालयों** का निर्माण किया है। **इसके अतिरिक्त वर्ष 2005-12 से 2014-2024** तक न्यूनतम जीरो बैलेंस वाले **बैंक खाते 500 गुना बढ़े हैं।**
  - ❑ यूपीए सरकार ने केवल **164 जन औषधि स्टोर खोले, जिनमें से केवल 87 ही चालू थे**। हालांकि, मोदी सरकार के कार्यकाल **वर्ष 2014-2023 तक 10,000 जन औषधि स्टोरों** का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।
- **वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 तक औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति गिरकर 5% हो गई,** जबकि वित्त वर्ष 2004 **से वित्त वर्ष 2014 तक यह 8.2% थी। मोदी सरकार के कार्यकाल में** भारत के **सेवा क्षेत्र में 97% की वृद्धि** हुई है, जो **36% की वैश्विक सेवा निर्यात** वृद्धि को पार कर गया है, जो दुनिया भर में इस क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है।
- वित्तीय **वर्ष 2015 और 2023 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग दोगुना हो चुका है,** इसे पी.एल.आई के माध्यम से रणनीतिक उदारीकरण के द्वारा सक्षम बनाया गया जिसने कई

	संप्रग सरकार		एनडीए सरकार	
योजना	**अवधि**	**परिणाम**	**अवधि**	**परिणाम**
किफायती आवास- ग्रामीण	2003-14	2.1 करोड़	2016-2024	2.6 करोड़
शौचालयों का निर्माण	2011-14	1.8 करोड़ शौचालय निर्मित	2014-2024	11.5 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किफायती पेंशन	2011-2014	36.4 लाख लाभार्थी	2015-2023	6.1 करोड़ लाभार्थी
न्यूनतम शून्य राशि वाले बैंक खाते	2005-2012	10.3 करोड़ खाते	2014-2024	51.6 करोड़ खाते
ग्रामीण विद्युतीकरण	2005-2014	2.15 करोड़ आवास	2017-2022	2.86 करोड़ आवास विद्युतीकृत
किफायती दवाइयां	2008-2014	164 जन औषधि भंडार खोले गए, जिनमें से 87 कार्यात्मक	2014-2023	10,000 भंडार खोले गए
ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क	2011-2014	6577 किमी ऑप्टिकल फाइबर लगाया गया	2015-2023	6.8 लाख किमी ऑप्टिकल फाइबर लगाया गया
गरीबों के लिए मातृत्व लाभ	2010-2013	53 जिलों में 9.9 लाख लाभार्थी	2017-2023	पूरे भारत में 3.59 करोड़ लाभार्थी

क्षेत्रों में स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई) की अनुमति दी।

- मोदी सरकार ने सफलतापूर्वक **जीएसटी को लागू** करके यूपीए सरकार के एक दशक लंबे संघर्ष का समाधान किया है। हस्तांतरण हिस्सेदारी का **30-32% से 41-42%** तक बढ़ना, सहकारी संघवाद के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। राज्यों को समर्पित संसाधनों की कुल मात्रा लगभग चार गुना तक बढ़ गई है जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% है।
- वित्तीय **वर्ष 2023 में भारत ने 893.19 मिलियन टन का ऐतिहासिक कोयला उत्पादन स्तर** प्राप्त किया और वित्तीय वर्ष 2014 की तुलना में कुल कोयला उत्पादन में 57.8% की वृद्धि हुई है।
- मोदी सरकार के अंतर्गत सितंबर, 2023 में **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति कम होकर 3.2% हो गई**, जबकि **संपत्ति पर रिटर्न 2013-14 में 0.50% से बढ़कर 2022-23 में 0.79% हो गया** और **इक्विटी पर रिटर्न** बढ़कर **12.35%** हो गया है।
- भारत ने घोटालों और आधुनिक तकनीकों तक सीमित पहुंच के युग से लेकर सस्ते दरों पर व्यापक 4जी कवरेज और 2023 में दुनिया के सबसे तेजी से 5जी लागू करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसी प्रकार, देश का **संसाधन आवंटन में अपारदर्शी प्रथाओं**, जैसेकि कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला आदि से निकलकर पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ नीलामी प्रणाली की ओर **परिवर्तन हुआ** है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक वित्त को मजबूत करना है। इसके अतिरिक्त, **जी.आई.एफ.टी, आई.एफ.एस.सी में एक पारदर्शी बुलियन एक्सचेंज** स्थापित करने के लिए **विशेष सोने के आयात लाइसेंस देने में बदलाव लाना** सभी के लिए निष्पक्ष और सुलभ आर्थिक प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यूपीए सरकार ने एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था को कमजोर अर्थव्यवस्था में बदला

- यूपीए सरकार को अधिक सुधारों के लिए तैयार एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, लेकिन उसने अपने 10 वर्षों में इसे लचर अर्थव्यवस्था बना दिया।
- विडंबना यह है कि यूपीए नेतृत्व, जो शायद ही कभी 1991 के सुधारों का श्रेय लेने में विफल रहता है, उसने 2004 में सत्ता में आने के बाद उन्हें छोड़ दिया।
- 2014 में बैंकिंग संकट बहुत बड़ा था और दांव पर लगी कुल राशि बहुत बड़ी थी। मार्च 2004 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सकल अग्रिम केवल 6.6 लाख करोड़ रुपये था। मार्च 2012 में, यह 39.0 लाख करोड़ रुपये था।
- 2013 में जब अमेरिकी डॉलर तेजी से बढ़ा। यूपीए सरकार ने बाहरी और व्यापक आर्थिक स्थिरता से समझौता किया था और 2013 में मुद्रा में गिरावट आई थी। 2011 और 2013 के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 36 प्रतिशत गिर गया।
- प्रवासी भारतीयों के लिए 'फॉरेन करेंसी नॉन-रेसिडेंट' (एफसीएनआर (बी)) डिपॉजिट विंडो वास्तव में मदद के लिए एक गुहार थी, जब विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी हुई थी।
- यूपीए सरकार के तहत विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई, 2011 में लगभग 294 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर अगस्त, 2013 में लगभग 256 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। सितंबर, 2013 के अंत तक आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार 6 महीने से थोड़े अधिक समय के लिए ही पर्याप्त था, जबकि यह मार्च, 2004 के अंत में 17 महीने के लिए पर्याप्त था।
- 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर यूपीए सरकार की प्रतिक्रिया- स्पिल-ओवर प्रभावों से निपटने के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज, उस समस्या से कहीं अधिक खराब थी जिसका वह समाधान करना चाहती थी।
- यह वित्त पोषण और रखरखाव की केंद्र सरकार की क्षमता से कहीं परे था। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोत्साहन का उन परिणामों से कोई संबंध नहीं दिख रहा है, जो इसे हासिल करने की कोशिश की गई थी। इसका कारण यह था कि हमारी अर्थव्यवस्था संकट से अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं हुई थी। जीएफसी के दौरान वित्त वर्ष 2009 में भारत की वृद्धि धीमी होकर 3.1 प्रतिशत हो गई, लेकिन वित्त वर्ष 2010 में तेजी से बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गई।
- यूपीए सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों, उर्वरक कंपनियों और भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां (तेल बॉन्ड) वित्त वर्ष 2006 से वित्त वर्ष 2010 तक पांच वर्षों में कुल 1.9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की थीं।
- प्रत्येक वर्ष के लिए सब्सिडी बिल में उन्हें शामिल करने से राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा बढ़ जाता, लेकिन उन्हें छुपाया गया।
- अपने राजकोषीय कुप्रबंधन के परिणामस्वरूप यूपीए सरकार का राजकोषीय घाटा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक हो गया, और बाद में उसे 2011-12 के बजट की तुलना में बाजार से 27 प्रतिशत अधिक उधार लेना पड़ा।
- अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय घाटे का बोझ सहन करना बहुत भारी हो गया। वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के प्रभाव को निर्मूल करने के बहाने यूपीए सरकार ने अपनी उधारी का विस्तार किया और इसी बात पर अड़ी रही। यूपीए सरकार ने न केवल बाजार से भारी मात्रा में उधार लिया, बल्कि जुटाई गई धनराशि का उपयोग अनुत्पादक तरीके से किया।
- बुनियादी ढांचे के निर्माण की गंभीर उपेक्षा की गई, जिससे औद्योगिक और आर्थिक विकास में गिरावट आयी।

- एक जनहित याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए हलफनामे में यूपीए सरकार ने कहा कि लगभग 40,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े गए।
- 1997 से 2002 तक एनडीए शासन के दौरान 24,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े गए।
- इसके बाद, यूपीए के पिछले दस वर्षों (2004-14) में लगभग 16,000 किलोमीटर ही जोड़े गए।
- रिजर्व बैंक की रिपोर्टों ने यूपीए सरकार द्वारा अत्यधिक राजस्व व्यय की ओर भी इशारा किया। खराब नीति नियोजन और कार्यान्वयन के कारण यूपीए के वर्षों के दौरान कई सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च नहीं किया गया।
- यूपीए सरकार के तहत स्वास्थ्य व्यय भारतीय परिवारों के लिए एक चिंता का विषय बना रहा।
- यह है कि वित्त वर्ष 2014 में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) का 64.2 प्रतिशत था (वित्त वर्ष 2005 में टीएचई के प्रतिशत के रूप में 69.4 प्रतिशत ओओपीई से थोड़ा सुधार के साथ) इसका मतलब है कि स्वास्थ्य व्यय भारतीय नागरिकों की जेब खाली करता रहा।
- दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास के प्रति विचार की ऐसी कमी थी कि रक्षा तैयारियों का महत्वपूर्ण मुद्दा भी नीतिगत पंगुता के कारण बाधित हो गया था।
- यूपीए सरकार के शासन का दशक (या उसका अभाव) नीतिगत दुस्साहस और 2-जी घोटाले और कोयला घोटाले जैसे कांडों से भरा रहा।
- यूपीए सरकार को जुलाई 2012 में हमारे इतिहास की सबसे बड़ी बिजली कटौती के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिसने 62 करोड़ लोगों को अंधेरे में छोड़ दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया।
- कोयला और गैस जैसे ईंधन की कमी के कारण 24,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी होने के बावजूद देश में ऐसा अंधेरा छा गया।
- 2जी घोटाले और नीतिगत पंगुता के कारण भारत के दूरसंचार क्षेत्र ने एक कीमती दशक गंवा दिया। यूपीए शासन में स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था और 2008-09 तक के वर्षों में इसका अक्सर दुरुपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप '2जी घोटाला' हुआ।
- यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई 80:20 स्वर्ण निर्यात-आयात योजना इस बात का उदाहरण है कि कैसे अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष हितों की पूर्ति के वास्ते सरकारी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को तबाह कर दिया गया।
- यूपीए सरकार का कार्यकाल नीतिगत गतिहीनता के उदाहरणों से भरा रहा। कैबिनेट सचिव ने 2013 में इसकी चर्चा की थी। यूपीए सरकार साझा उद्देश्यों को समझ नहीं पाई और दायरे, उद्देश्य और कार्यान्वयन की जिम्मेदारियों में व्यापक अंतर-मंत्रालयी मतभेद थे।

घरेलू निवेशक भी विदेश जाने लगे

- दुनिया भर में निवेशक व्यापार करने में आसानी चाहते थे, जबकि यूपीए सरकार ने नीतिगत अनिश्चितता और परेशानी प्रदान की। यूपीए सरकार के अंतर्गत निराशाजनक निवेश माहौल के कारण घरेलू निवेशक विदेश जाने लगे।
- यूपीए सरकार ने पिछली सरकार द्वारा लाए गए सुधारों का लाभ उठाया, लेकिन उन महत्वपूर्ण सुधारों को पूरा करने में

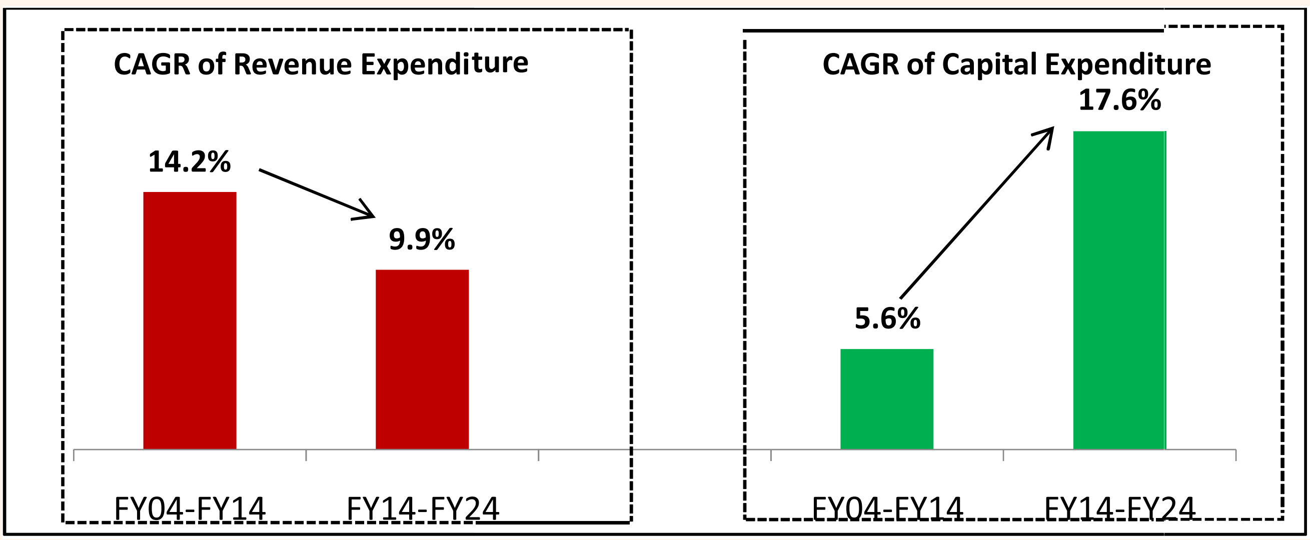

असफल रही जिनका उसने वादा किया था। भारत में डिजिटल सशक्तीकरण के प्रतीक 'आधार' को भी यूपीए के हाथों नुकसान उठाना पड़ा है।

- बड़ी संख्या में विकास कार्यक्रम और परियोजनाएं खराब तरीके से लागू की गईं।
- जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली, तो अर्थव्यवस्था में कोई अर्थपूर्ण, अपेक्षित या उपयोगी निष्कर्ष निकलता नहीं दिखाई दे रहा था। भारत के नीति नियोजकों और देश की प्राथमिकताओं के बीच संबंध इस कदर टूटा हुआ था कि लोगों ने 2014 के आम चुनावों में एनडीए को बागडोर संभालने के लिए भारी जनादेश दिया।
- वित्त वर्ष 2011 से 2014 के दौरान कौशल विकास के लिए 57 से 83 प्रतिशत भागीदार अपना लक्ष्य पूरा करने में विफल रहे।
- यूपीए सरकार का दशक एक गंवा दिया गया दशक था क्योंकि वह मजबूत बुनियादी अर्थव्यवस्था और वाजपेयी सरकार द्वारा छोड़ी गई सुधारों की गति का लाभ उठाने में विफल रही। यूपीए सरकार में बार-बार नेतृत्व का संकट पैदा होता रहा।
- यूपीए सरकार के आर्थिक और राजकोषीय कुप्रबंधन ने अंततः अपने कार्यकाल के अंत तक भारत की विकास संभावना को खोखला कर दिया था।
- जैसे ही 2014 में हमारी सरकार ने सता संभाली, हमने व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं में सुधार और बदलाव की तत्काल आवश्यकता को पहचाना, ताकि भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ने में मदद मिल सके और साथ ही, इसकी व्यापक आर्थिक नींव को भी सहारा दिया जा सके।
- शासन के हमारे नए प्रतिमान के अंतर्गत भारत ने डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करने से लेकर खुले में शौच के उन्मूलन और स्वदेशी टीकों का उपयोग करके पूरी पात्र आबादी का सफलतापूर्वक टीकाकरण करने से लेकर निर्यात में व्यापक विविधता लाने तक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
- साथ-साथ, हमने अर्थव्यवस्था और व्यापार क्षेत्र को भी मजबूत किया है। हमारी सरकार के शुरुआती वर्षों में ही एक व्यापक सुधार प्रक्रिया की नींव रखी गई।
- आईएमएफ आर्टिकल IV रिपोर्ट (2015) में उल्लेख किया गया है— "भारत के निकट अवधि के विकास संभावना में सुधार हुआ है और जोखिमों का संतुलन अब अधिक अनुकूल है, बढ़ी हुई राजनीतिक निश्चितता, कई नीतिगत कार्रवाइयों, व्यापार आत्मविश्वास में सुधार, वस्तुओं के आयात की कीमतों में कमी और बाहरी अति संवेदनशीलता में कमी से मदद मिली है।"
- दो साल बाद अपनी 2017 आर्टिकल IV रिपोर्ट में आईएमएफ ने भारत के बारे में अपने आशावाद को और उन्नत करते हुए कहा कि प्रमुख सुधारों के कार्यान्वयन, आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को कम करने और उचित राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के कारण मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं में सुधार हुआ है जिसने व्यापक आर्थिक स्थिरता बढ़ाई है।
- सुधार प्रक्रिया की शुरुआत ने हमारी सरकार के शुरुआती वर्षों में निवेश माहौल में सुधार और अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल दृष्टिकोण तैयार करके सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिया।

निवेशक की भावनाओं को फिर से जगाना

- हमारी सरकार 'प्रकृति' और 'प्रगति' को संतुलित करने की सच्ची भावना को समझती है जो 2011 के नियमों में पूरी तरह से गायब थी। हमारी सरकार द्वारा किए गए सुधार उपायों ने अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की निवेश संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा दिया है।
- प्रसिद्ध निवेशक और फंड मैनेजर मार्क मोबियस का एक डालिया बयान, जिन्होंने यह टिप्पणी की— "भारत निवेशकों को लुभाकर और उन्हें बड़े नतीजों के वादे से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मैं भी इसकी विशाल विकास संभावना से मंत्रमुग्ध हूं।"

सशक्त और प्रभावी संवितरण के माध्यम से लोक कल्याण

- कल्याण के माध्यम से सशक्तीकरण हमारी सरकार का ध्येय

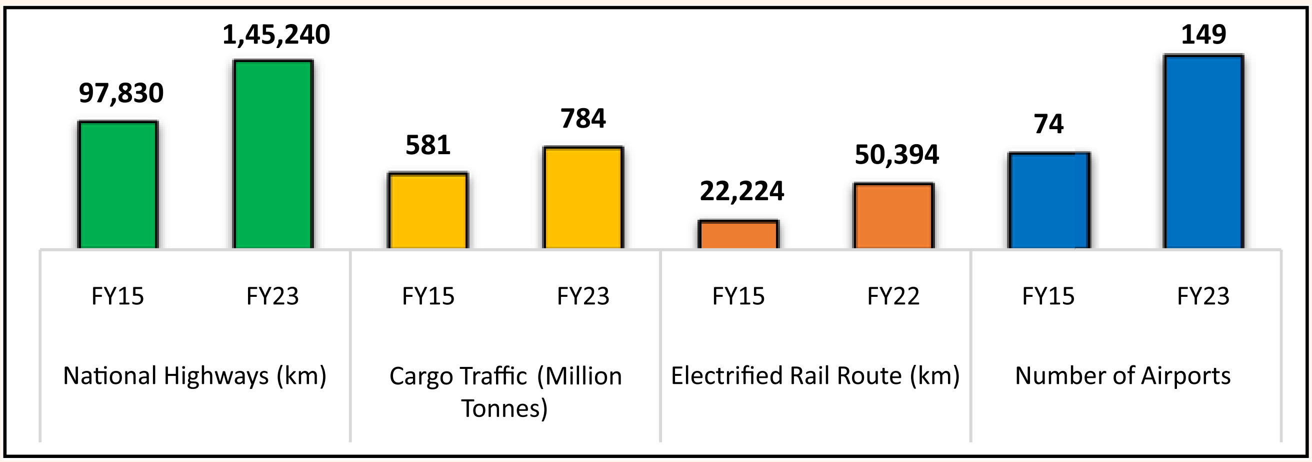

एक दशक में फ़ैजाइल-फाइव से शीर्ष-पांच पर

- आर्थिक कुप्रबंधन ने विकास की संभावनाओं को अवरुद्ध कर दिया और भारत एक 'फ़ैजाइल' अर्थव्यवस्था बन गया।
- मॉर्गन स्टेनली ने भारत को 'फ्रैजाइल फाइव' के स्तर पर रखा था— एक समूह जिसमें कमजोर व्यापक आर्थिक बुनियादी नींव वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बाहरी घाटा और सार्वजनिक वित्त की खराब स्थिति शामिल है।
- सच्चाई यह है कि अर्थव्यवस्था 2004 में 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 2014 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकी, जो कि अल्पकालिक, गुणात्मक रूप से हीन स्थिति को उजागर करती है।
- 2014 में जब से हमारी सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से भारतीय अर्थव्यवस्था में कई संरचनात्मक सुधार हुए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था के व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांत मजबूत हुए हैं।
- इन सुधारों के परिणामस्वरूप भारत लगभग एक दशक में ही 'फैजाइल फाइव' के स्तर से 'टॉप फाइव' के स्तर में आ गया, क्योंकि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच अर्थव्यवस्था कहीं अधिक लचीले अवतार में बदल गई थी।
- हमारी सरकार की "राष्ट्र प्रथम" की कल्पना ने भारत के बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की गुणवत्ता को बदल दिया है, जो देश के लिए निवेश आकर्षित करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए निर्णायक होगा।
- उदाहरण के लिए, जब हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2015 में कार्यभार संभाला था, तब राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति 12 किमी/प्रतिदिन थी। वित्त वर्ष 2023 में निर्माण की गति 2.3 गुना से अधिक बढ़कर 28 किमी/प्रतिदिन हो गई।
- इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोपरि रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद को यूपीए सरकार द्वारा प्राथमिकता नहीं दी गई थी। हमारी सरकार द्वारा इन पर बल दिया गया है।

रहा है। हमने बुनियादी सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच को प्राथमिकता देते हुए 'सबका साथ, सबका विकास' की विचारधारा को अपनाया और इस विचारधारा को साकार करने में भागीदारी, मिशन-मोड दृष्टिकोण अपनाया।

- हमारी सरकार ने प्रौद्योगिकी-आधारित लक्ष्यीकरण और निगरानी तंत्र लागू करके यूपीए सरकार से त्रस्त चुनौतियों का समाधान किया है।
- यूपीए सरकार के कार्यक्रम वितरण में काफी सुधार करने के अलावा, हमारी सरकार ने भारत की विकास क्षमता को उभारने के लिए कई नीतिगत नवाचार भी किए।
- पीएम-किसान सम्मान निधि ने किसानों को सशक्त बनाया और उधारकर्ता-ऋणदाता संबंधों को नुकसान पहुंचाए बिना उनकी आय में सुधार किया।
- वर्ष 2014 में यूपीए सरकार से प्राप्त उच्च मुद्रास्फीति की स्थायी चुनौती से निपटने के लिए, हमारी सरकार ने जवाबदेह राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के कार्यान्वयन के द्वारा कार्यनीतिक रूप से समस्याओं मूल कारणों का पता लगाया था।
- राजकोषीय सुधार से सरकार के व्यय निर्णय को सीमित किया गया है। वर्ष 2016 में सरकार ने लक्षित मुद्रास्फीति को 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बैंड के अंदर रखने के लिए आरबीआई को अधिदेश दिया था। वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2023 के बीच औसत वार्षिक मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2004 और वित्त वर्ष 2014 के बीच 8.2 प्रतिशत की औसत मुद्रास्फीति से 5.0 प्रतिशत कम हो गई थी।
- हमारी सरकार द्वारा यूपीए सरकार से प्राप्त उच्च विदेशी भेद्यता को नियंत्रित करने के लिए अनुकूल प्रयास किए गए हैं।
- हमारी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों को बहाल किए जाने के कारण रुपये ने वैश्विक आघातों के दौरान लचीलापन प्रदर्शित किया।
- वर्ष 2013 में फेडरल रिजर्व की घोषणा के चार महीनों के भीतर ही रुपये में डॉलर के मुकाबले 14.9 प्रतिशत की गिरावट आई थी।
- इसके विपरीत टेपर 2 की घोषणा के बाद चार महीनों के भीतर 2021 में रुपये में 0.7 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई।
- हमारी सरकार ने न केवल चालू खाते को विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधित किया, बल्कि आसान और सुविधापूर्ण वित्त पोषण के माध्यम से अधिक स्थिर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को सुनिश्चित किया।
- वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2014 के बीच जुटाए गए 305.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल एफडीआई के विपरीत हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2023 के बीच नौ वर्षों में इस राशि का लगभग दोगुना (596.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) संग्रह किया है।
- परिणामस्वरूप, भारत का बाह्य क्षेत्र मार्च 2014 में 303 बिलियन अमेरिकी डॉलर (आयात के 7.8 महीनों के बराबर) से जनवरी 2024 में 617 बिलियन अमेरिकी डॉलर (आयात के 10.6 महीने) तक वृद्धि विदेशी मुद्रा प्रारेक्षित निधि (फॉरेक्स रिजर्व) के साथ अधिक सुरक्षित है।

लोक वित्तः खराब स्थिति से मजबूत स्थिति तक की यात्रा

- जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो लोक वित्त अच्छी अवस्था में नहीं था। लोक वित्त को अच्छी अवस्था में लाने के लिए हमारी सरकार ने भारत की राजकोषीय प्रणाली को बदलने के लिए संवर्धित करों और व्यय परितंत्र में बहुत अधिक बदलाव किए हैं।
- पिछली परिपाटी से हटकर, सीमा से नीचे (बिलो-दी-लाइन) वित्तपोषण का अब पारदर्शी रूप से खुलासा किया जा रहा है। अब तक इस सरकार ने 2014 से पहले सब्सिडी के नकद भुगतान के बदले में तेल विपणन कंपनियों, उर्वरक कंपनियों और भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के लिए मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान की दिशा में पिछले दस वर्षों में लगभग 1.93 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
- 2025-2027 के दौरान यह सरकार शेष बकाया देयताओं और उस पर ब्याज के लिए आगे 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- केंद्र सरकार के बाजार उधार, जो यूपीए के कार्यकाल के दौरान अभूतपूर्व दरों पर बढ़े थे, को हमारी सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था।
- हमारी सरकार द्वारा व्यय की गुणवत्ता में किए गए सुधार हमारी राजकोषीय नीति की आधारशिला है।
- बजटीय पूंजीगत व्यय में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए बिना वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2024 (आरई) तक पांच गुना से अधिक वृद्धि हुई है।

पिछले दशक में मजबूत राजस्व वृद्धि के साथ कर-इकोसिस्टम में सुधार

- जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत एक बेहद ही जरूरी संरचनात्मक सुधार था। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत से पहले, 440 से अधिक कर की दरों व उत्पाद शुल्क का प्रावधान था और इन दरों को प्रशासित करने वाली विभिन्न एजेंसियों की अनुपालन आवश्यकताओं का मतलब था कि भारत का आंतरिक व्यापार न तो स्वतंत्र था और न ही एकीकृत था।
- सुधारों के कार्यान्वयन से उन 29 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों को एकीकृत करना संभव हुआ था, जो अपनी अलग-अलग कर संरचनाओं के कारण अपने आप में आर्थिक क्षेत्र थे। नई कर संरचना की विशेषता राजनीतिक सर्वसम्मति निर्माण और जीएसटी परिषद् की संप्रभुता है, जो सहकारी संघवाद के प्रमुख उदाहरण हैं। पिछले एक दशक में हुए दूरगामी कर सुधारों ने प्रभावी प्रणालियां स्थापित की हैं जिनसे राजस्व संग्रह और अनुपालन में सुधार हुआ है।
- वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2024 तक संशोधित अनुमान के लिए औसत कर-जीडीपी अनुपात लगभग 10.9 प्रतिशत है, जो 2004-14 के दौरान के दस वर्ष के 10.5 प्रतिशत के औसत से अधिक है। ऐसा कम कर दरों और कोविड-19 महामारी के दौरान दी गई व्यापक राहतों के बावजूद संभव हुआ है।
- इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि राज्य विकास में समान भागीदार है, हमारी सरकार ने सहकारी संघवाद की भावनाओं के अनुरूप 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया।

दोनों व्यवस्थाओं में राज्यों को किए गए अंतरण की तुलना

(क) कर अंतरण और एफसी अनुदान के माध्यम से राज्यों को 3.8 गुना अधिक संसाधन

(ख) कर अंतरण और एफसी अनुदान के माध्यम से राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत अंक के अतिरिक्त संसाधन

- बदलते परिवेश के काल में केंद्र ने राज्यों का भरपूर सहयोग किया है। कोयला क्षेत्र में अक्षमताओं को दूर करने और प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता बढ़ाने हेतु हमारी सरकार द्वारा पिछले दस वर्षों में कई सुधार किए गए हैं।
- सत्ता में आने के बाद हमारी सरकार ने देश के कोयला संसाधनों और ऊर्जा सुरक्षा के पारदर्शी आवंटन को सुनिश्चित करने हेतु कोयला खान विशेष प्रावधान (सीएमएसपी) अधिनियम 2015 को तेजी से लागू किया। किए गए कई अन्य उपायों में पहली बार कोयला ब्लॉक की नीलामी, वाणिज्यिक कोयला खनन, कोयला लिंकेज का युक्तीकरण, कोयले की ई-नीलामी के लिए एकल खिड़की आदि शामिल हैं।
- हमारी सरकार ने देश के बिजली क्षेत्र में मौजूद कई समस्याओं को हल किया है, इस प्रकार इसे बिजली की कमी वाली स्थिति से पर्याप्त बिजली वाली स्थिति में बदल दिया है।

दूरसंचार क्षेत्र में बेहतर प्रशासन की शुरुआत

- 2014 के बाद से हमारी सरकार ने दूरसंचार के बाजार में स्थितियों को ठीक करने और इस क्षेत्र में नीतिगत स्पष्टता की कमी के कारण उत्पन्न विफलताओं को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसने स्पेक्ट्रम नीलामी, व्यापार और साझाकरण के पारदर्शी तरीके लाए जिससे स्पेक्ट्रम का अधिकतम उपयोग संभव हो सका। 2022 में 5जी नीलामी के आयोजन ने अब तक के उच्चतम नीलामी मूल्य पर स्पेक्ट्रम की उच्चतम मात्रा यानी 52 गीगाहर्ट्ज़ आवंटित करके दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लिए समग्र स्पेक्ट्रम उपलब्धता में वृद्धि की।
- इसके अलावा, टीएसपी के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह ने उन्हें 5जी तकनीक में पूंजी निवेश करने में सक्षम बनाया, जिससे देश में 5जी नेटवर्क की शुरुआत हुई, जिसे दुनिया में सबसे तेज 5जी शुरुआत के रूप में स्वीकार किया गया है। ■

प्रधानमंत्री ने 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक को किया संबोधित

पिछले 5 वर्षों का मंत्र 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन': नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 फरवरी को 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक को संबोधित किया। सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का अवसर भारत के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महत्वपूर्ण निर्णय लेने और देश को दिशा देने में 17वीं लोकसभा के सभी सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज का दिन राष्ट्र को अपनी वैचारिक यात्रा और उसकी बेहतरी के लिए समय समर्पित करने का विशेष अवसर है। श्री मोदी ने कहा, "सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन पिछले 5 वर्षों से मंत्र रहा है" और इसे आज पूरा देश अनुभव कर सकता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत के लोग 17वीं लोकसभा को उसके प्रयासों के लिए आशीर्वाद देना जारी रखेंगे।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री मोदी ने सदन के सभी सदस्यों के योगदान को रेखांकित करते हुए उनके प्रति और विशेषकर सदन के लोकसभा अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष को धन्यवाद दिया और सदन को हमेशा मुस्कुराते हुए, संतुलित और निष्पक्ष तरीके से चलाने के लिए उनकी सराहना की।

श्री मोदी ने इस दौरान मानवता पर आई सदी की सबसे बड़ी आपदा यानी कोरोना महामारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवस्थाएं की गईं और सदन में देश का काम नहीं रुकने दिया गया। उन्होंने सांसद निधि को छोड़ने और महामारी के दौरान सदस्यों द्वारा अपने वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती के लिए भी सदस्यों को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने सदस्यों के लिए सब्सिडी वाली कैंटीन सुविधाओं को हटाने के लिए भी लोकसभा अध्यक्ष को धन्यवाद दिया, जिस पर लोगों की प्रतिकूल टिप्पणियां आती थीं।

नया संसद भवन एवं सेंगोल

श्री मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण के बारे में सभी सदस्यों को एकमत करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की सराहना की, जिसके चलते नए संसद भवन का निर्माण हुआ और अब वर्तमान सत्र यहां हो रहा है।

नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि यह भारत की विरासत के पुनर्ग्रहण और स्वतंत्रता के पहले क्षण की याद का प्रतीक है। उन्होंने सेंगोल को वार्षिक समारोह का हिस्सा बनाने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले की भी सराहना की और कहा कि यह भविष्य की पीढ़ियों को उस क्षण से जोड़ेगा, जब भारत ने प्रेरणा का स्रोत होने के साथ-साथ स्वतंत्रता हासिल की थी।

जी20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता

श्री मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता द्वारा लाई गई वैश्विक मान्यता का उल्लेख किया और जिसके लिए प्रत्येक राज्य ने अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इसी तरह, पी20 शिखर सम्मेलन ने लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की साख को मजबूत किया।

प्रधानमंत्री ने भाषण और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करके राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों में अनुष्ठानिक वर्षगांठ पुष्पांजलि के विस्तार की ओर भी इशारा किया। हर राज्य से शीर्ष 2 दावेदार दिल्ली आते हैं और गणमान्य व्यक्ति के संबंध में बात करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि इसने लाखों छात्रों को देश की संसदीय परंपरा से जोड़ा। प्रधानमंत्री ने संसद पुस्तकालय को आम नागरिकों के लिए खोलने के महत्वपूर्ण निर्णय का भी उल्लेख किया।

श्री मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पेश की गई पेपरलेस संसद और डिजिटल प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की अवधारणा के बार में बात करते हुए इस पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री ने 17वीं लोकसभा की उत्पादकता को लगभग 97 प्रतिशत तक ले जाने के लिए सदस्यों के संयुक्त प्रयास और लोकसभा अध्यक्ष के कौशल तथा सदस्यों की जागरूकता को श्रेय दिया। भले ही यह एक उल्लेखनीय संख्या है, श्री मोदी ने सदस्यों से संकल्प लेने और 18वीं लोकसभा की शुरुआत में उत्पादकता को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने सदन को सूचित किया कि 7 सत्र 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादक रहे हैं जब सदन ने आधी रात तक अध्यक्षता की और सभी सदस्यों को अपने मन की बात कहने

की अनुमति दी। श्री मोदी ने बताया कि 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में 30 विधेयक पारित हुए जो एक रिकॉर्ड है।

आजादी का अमृत महोत्सव

आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान सांसद होने की खुशी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने महोत्सव को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक जन आंदोलन बनाने के लिए सदस्यों की प्रशंसा की। इसी तरह, संविधान के 75वें साल ने भी सभी को प्रेरित किया।

श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव को उस दौर के गेम-चेंजर सुधारों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, "हम बड़े संतोष के साथ कह सकते हैं कि 17वीं लोकसभा के माध्यम से कई चीजें पूरी हुईं, जिनका पीढ़ियां इंतजार करती थीं।" श्री मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से संविधान का पूरा वैभव प्रकट हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे संविधान निर्माताओं को खुशी हुई होगी। श्री मोदी ने कहा, "आज सामाजिक न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता जम्मू-कश्मीर के लोगों तक पहुंच रही है।"

आतंकवाद के संकट को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन द्वारा बनाए गए कड़े कानूनों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को सशक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे उन लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और आतंकवाद का पूर्ण खात्मा निश्चित रूप से पूरा होगा।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित

श्री मोदी ने नए कानूनों को अपनाने का जिक्र करते हुए कहा, "हम गर्व से कह सकते हैं कि यह देश 75 वर्षों तक दंड संहिता के तहत जरूर रहा है मगर अब हम न्याय संहिता के तहत रह रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को भी धन्यवाद दिया। भले ही पहला सत्र बाकी सत्रों की तुलना में छोटा था, श्री मोदी ने कहा कि यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने का परिणाम है कि आने वाले समय में सदन महिला सदस्यों से भर जाएगा। उन्होंने 17वीं लोकसभा में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए तीन तलाक को खत्म करने की भी बात कही।

2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प

श्री मोदी ने देश के लिए अगले 25 वर्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश ने अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया है। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किए गए नमक सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलन के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि ये घटनाएं इसकी शुरुआत के समय महत्वहीन हो सकती थीं, लेकिन उन्होंने अगले 25 वर्षों के लिए नींव तैयार की, जिससे 1947 में भारत की आजादी हुई। उन्होंने कहा कि ऐसी ही भावना देश के भीतर भी महसूस की जा सकती है, जहां हर व्यक्ति ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है।

युवाओं के लिए पहल और कानूनों की ओर इशारा करते हुए श्री मोदी ने पेपर लीक की समस्या के खिलाफ मजबूत कानून का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम के दूरगामी महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह अधिनियम भारत को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगा।

यह देखते हुए कि 21वीं सदी में दुनिया में बुनियादी ज़रूरतें बदल गई हैं श्री मोदी ने डेटा के मूल्य का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के पारित होने से वर्तमान पीढ़ी के डेटा की सुरक्षा हुई है और दुनिया भर से इसमें रुचि भी पैदा हुई है। भारत में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश की विविधता और देश के भीतर उत्पन्न होने वाले विविध डेटा पर प्रकाश डाला।

श्री मोदी ने सुरक्षा के नए आयामों का जिक्र करते हुए समुद्री, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा के महत्व पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, "हमें इन क्षेत्रों में सकारात्मक क्षमताएं पैदा करनी होंगी और नकारात्मक ताकतों से निपटने के लिए साधन भी विकसित करने होंगे।" उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष सुधार दीर्घकालिक प्रभाव के साथ दूरदर्शी हैं।

आर्थिक सुधार

17वीं लोकसभा द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों पर बात करते हुए श्री मोदी ने बताया कि आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए हजारों अनुपालन हटा दिए गए थे। प्रधानमंत्री ने 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' में विश्वास दोहराते हुए कहा कि नागरिकों के जीवन में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप सुनिश्चित करके किसी भी लोकतंत्र की क्षमताओं को अधिकतम किया जा सकता है।

श्री मोदी ने कहा कि 60 से अधिक अप्रचलित कानून हटाये गये। उन्होंने कहा कि कारोबार सुगमता में सुधार के लिए यह जरूरी है। उन्होंने नागरिकों पर भरोसा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जन विश्वास अधिनियम ने 180 गतिविधियों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। मध्यस्थता अधिनियम ने अनावश्यक मुकदमेबाजी से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में मदद की है।

ट्रांसजेंडर समुदाय की दुर्दशा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने समुदाय के लिए अधिनियम लाने के लिए सदस्यों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कमजोर वर्गों के लिए संवेदनशील प्रावधान वैश्विक सराहना का विषय हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों को एक पहचान मिल रही है और वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उद्यमी बन रहे हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में ट्रांसजेंडर का भी नाम शामिल है।

श्री मोदी ने उन सदस्यों के लिए गहरा दुःख व्यक्त किया, जिन्होंने कोविड महामारी के कारण अपनी जान गंवा दी। कोविड के चलते सदन की कार्यवाही लगभग 2 वर्षों तक प्रभावित रही।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री राम मंदिर अयोध्या धाम प्राण प्रतिष्ठा पर प्रस्ताव पारित किया तथा प्रधानमंत्री को दी हार्दिक बधाई

कैबिनेट ने 24 जनवरी को श्री राम मंदिर अयोध्या धाम प्राण प्रतिष्ठा पर एक प्रस्ताव पारित किया तथा प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई दी। प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी, आपने अपने कार्यों से इस राष्ट्र का मनोबल ऊंचा किया है और सांस्कृतिक आत्मविश्वास मजबूत किया है। प्रस्ताव के मुख्य अंश निम्न हैंः

प्रधानमंत्री जी, आज की कैबिनेट ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कार्य तो कई बार हुए होंगे, परन्तु जब से यह कैबिनेट व्यवस्था बनी है और यदि ब्रिटिश टाइम से वायसराय की Executive Council का कालखण्ड भी जोड़ लें, तो ऐसा अवसर कभी नहीं आया होगा। क्योंकि 22 जनवरी, 2024 को आपके माध्यम से जो कार्य हुआ है, वह इतिहास में अद्वितीय है। वह इसलिए अद्वितीय है, क्योंकि यह अवसर शताब्दियों बाद आया है। हम कह सकते हैं कि 1947 में इस देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था और अब इसमें आत्मा की प्राण-प्रतिष्ठा हुई है। इससे सभी को आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई है।

आपने अपने उद्बोधन में कहा था कि भगवान राम भारत के प्रभाव भी हैं, और प्रवाह भी हैं, नीति भी हैं और नियति भी हैं और आज हम राजनैतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से कह सकते हैं कि भारत के सनातनी प्रवाह और वैश्विक प्रभाव के आधार स्तंभ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए नियति ने आपको चुना है।

वास्तव में, प्रभु श्रीराम भारत की नियति हैं और नियति के साथ, वास्तविक मिलन अब हुआ है। वास्तविकता में देखें तो कैबिनेट के सदस्यों के लिए यह अवसर जीवन में एक बार का अवसर नहीं, बल्कि अनेक जन्मों में एक बार का अवसर कहा जा सकता है।

प्रधानमंत्री जी, आपने अपने कार्यों से इस राष्ट्र का मनोबल ऊंचा किया है और सांस्कृतिक आत्मविश्वास मजबूत किया है। प्राण-प्रतिष्ठा में जिस तरह का भावनात्मक जन-सैलाब हमने देशभर में देखा, भावनाओं का ऐसा ज्वार हमने पहले कभी नहीं देखा।

भगवान राम के लिए जो जन-आंदोलन हमें देखने को मिला, वह एक नए युग का प्रवर्तन है। देशवासियों ने शताब्दियों तक इसकी प्रतीक्षा की और आज भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण-प्रतिष्ठा के साथ एक नए युग का प्रवर्तन हुआ है। आज यह एक नया नरेटिव सेट करने वाला जन-आंदोलन भी बन चुका है।

प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा अनुष्ठान तभी संपन्न हो सकता है, जब अनुष्ठान के कारक पर प्रभु की कृपा हो।

प्रधानमंत्री जी, श्रीराम जन्मभूमि का आंदोलन स्वतंत्र भारत का एकमात्र आंदोलन था, जिसमें पूरे देश के लोग एकजुट हुए थे। इससे करोड़ों भारतीयों की वर्षों की प्रतीक्षा और भावनाएं जुड़ी थीं। ■

शाश्वत है भारतीय लोकतंत्र की यात्रा

श्री मोदी ने कहा, "भारत के लोकतंत्र की यात्रा शाश्वत है और देश का उद्देश्य पूरी मानवता की सेवा करना है।" उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की जीवन शैली को स्वीकार कर रही है तथा सदस्यों से इस परंपरा को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

आगामी चुनावों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का एक स्वाभाविक और आवश्यक आयाम है। प्रधानमंत्री ने कहा, "मुझे विश्वास है कि चुनाव हमारे लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप होंगे।"

श्री मोदी ने 17वीं लोकसभा के कामकाज में योगदान के लिए सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर आज पारित प्रस्ताव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश की भावी पीढ़ियों को अपनी विरासत पर गर्व करने की संवैधानिक शक्तियां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इस मजबूत इरादे में 'संवेदना', 'संकल्प' और 'सहानुभूति' के साथ-साथ 'सबका साथ-सबका विकास' का मंत्र शामिल है। ■

यह हम सभी के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली समय है: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 10 फरवरी 2024 को श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह पर राज्यसभा में एक संक्षिप्त चर्चा में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि यह मंदिर मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में काम करेगा और वैश्विक संघर्षों के बीच हमें शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की याद दिलाता रहेगा। सदन ने 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में 'प्राण प्रतिष्ठा' की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि जिस दिन अयोध्या में नवनिर्मित भव्य मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वह दिन 'देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का दिन है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा।' उन्होंने आगे कहा कि मंदिर निर्माण कभी भी भाजपा के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था और पार्टी ने कभी इसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। यह भाजपा का आयोजन कैसे है?

'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह को भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम बनाने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद वह 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह का हिस्सा नहीं बन सके।

मंदिर न्यास ने ही प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था, तो यह भाजपा का आयोजन कैसे हो सकता है? लेकिन अगर कुछ लोगों की अंतरात्मा समारोह में शामिल होने से इनकार करने के लिए अब उन्हें कचोट रही है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता।

> **1989 में पालमपुर सम्मेलन के दौरान लिये गए अपने संकल्प में भाजपा ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करने करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी**

भाजपा ने अयोध्या का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की

उन्होंने कहा कि भाजपा ने अयोध्या के राम मंदिर पर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसके अभिषेक समारोह के दौरान पार्टी द्वारा एक भी राजनीतिक बयान नहीं दिया गया। श्री नड्डा ने कहा, "हमने इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की है। जब संसद में हमारे मात्र दो (1984) सदस्य थे, तब हम राम के लिए संघर्ष कर रहे थे और जब अब हमारे 300 सदस्य हो गये, तब भी हम राम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भाजपा की ओर से एक भी राजनीतिक बयान नहीं दिया गया। यह हमारा दृढ़ विश्वास, हमारी प्रतिबद्धता थी, जिसे हमने पूरा करने का प्रयास किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया श्री रामलला का अभिषेक

उन्होंने कहा कि एक समय वह भी था जब एक प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इंकार कर दिया था और अब वर्तमान समय है जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यम और नियम का पालन करते हुए संन्यासी का जीवन अपनाकर श्री रामलला का अभिषेक किया।

पालमपुर सम्मेलन के दौरान भाजपा ने लिया संकल्प

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 1989 में पालमपुर सम्मेलन के दौरान लिये गए अपने संकल्प में भाजपा ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करने करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। 'भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष को मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसका साक्षी रहा हूं और इससे मुझे शक्ति मिलती रही है।'

500 साल का संघर्ष

श्री नड्डा ने कहा कि 500 वर्षों के इस लंबे संघर्ष में कई पीढ़ियां बीत गईं। जन्मभूमि मंदिर को तोड़ने के बाद भगवान श्री राम का वनवास 500 वर्षों तक चला। इस व्यापक संघर्ष के बाद आज जब श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हैं, तो यह हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली समय है।

उन्होंने आगे कहा कि मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम इस देश की आत्मा, मूल्य और जीवन पद्धति हैं। भगवान राम कई धार्मिक ग्रंथों में मौजूद हैं तथा कई देशों ने धार्मिक दृष्टि से भी श्रीराम को अपनाया है। ■

22 जनवरी, 2024 दस हजार वर्षों तक ऐतिहासिक दिन रहेगाः अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 10 फरवरी को लोकसभा में ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर नियम 193 के तहत चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का दिन दस सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 22 जनवरी का दिन सन् 1528 से शुरू हुए संघर्ष और अन्याय के खिलाफ आंदोलन के अंत का दिन है। 22 जनवरी का दिन करोड़ों रामभक्तों की आकांक्षा और सिद्धि, पूरे भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण और महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का दिन मां भारती को विश्व गुरु बनने के मार्ग पर प्रशस्त होने का दिन है। श्री शाह ने श्रीराम मंदिर के लिए सन 1528 से 2024 तक संघर्ष करने वाले सभी योद्धाओं को नमन किया।

मुख्य बातें

- दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहां बहुमत समाज ने अपनी आस्था का निर्वहन करने के लिए इतनी लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ी
- श्रीराम मंदिर के लिए सन 1528 से 2024 तक संघर्ष करने वाले सभी योद्धाओं को नमन
- 22 जनवरी का दिन करोड़ों रामभक्तों की आकांक्षा व सिद्धि, भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण और महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है
- प्रभु श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मोदी जी की तपस्या सभी के लिए प्रेरणादायक है
- संघर्ष चला तो 'जय श्री राम' और मंदिर बना तो 'जय सियाराम', मोदी जी ने इस संघर्ष से भक्ति की यह यात्रा को पूरा किया

भारत की कल्पना प्रभु राम के बिना नहीं

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत की कल्पना प्रभु राम और राम चरित्र के बिना हो ही नहीं सकती और जो इस देश को पहचानना, जानना और जीना चाहते हैं, वो राम और रामचरित मानस के बिना ये कर ही नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि राम का चरित्र और राम इस देश के जनमानस का प्राण हैं। जो लोग राम के बिना भारत की कल्पना करते हैं, वो भारत को नहीं जानते और वे हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री शाह ने कहा कि हम सब उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो 1528 से अयोध्या में राम मंदिर देखना चाहते थे। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि रामजन्मभूमि का इतिहास बहुत लंबा है और अनेक राजाओं, संतों, संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों ने इसमें अपना योगदान दिया है।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर का भूमिपूजन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी उन्होने ही की। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जो कहते हैं, वो करते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने पूरी दुनिया में भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को उजागर किया है।

श्री शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने और राममंदिर के निर्माण के दौरान कई लोगों ने कहा कि देश में हिंसा होगी, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कोर्ट के निर्णय को भी जय-पराजय की जगह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में परिवर्तित करने का काम मोदी जी के दूरदर्शी विचार ने किया।

उन्होंने कहा कि जब मंदिर निर्माण के बाद भूमिपूजन का न्योता मिला, तब मोदी जी ने 11 दिन का कठोर व्रत रखा। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन तक शैय्या पर न सोकर, सिर्फ नारियल पानी पीकर और हर क्षण रामभक्ति में रच-बसकर राममय बनकर प्राण प्रतिष्ठा की।

श्री शाह ने कहा कि भारत में भक्ति आंदोलन कोई नई बात नहीं है। भारत के हजारों साल लंबे सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में एक नेता ने नेतृत्व के गुणों का परिचय देने का काम किया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस देश को बहुत लंबे समय से ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता ने श्री नरेन्द्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर देश की सभी चुनौतियों को समाप्त कर दिया। श्री शाह ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण पूरे समाज को जोड़कर सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अद्भुत उदाहरण है। ■

संसद का अंतरिम बजट सत्र- एक नजर

संसद का अंतरिम बजट सत्र 2024, 31 जनवरी, 2024 को शुरू हुआ तथा 10 फरवरी, 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र में ग्यारह दिनों की अवधि में नौ बैठकें हुईं। श्रीराम जन्मभूमि पर श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा के लिए सत्र को और एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया। सत्र के दौरान मोदी सरकार ने चार वर्गों— युवा, महिला, किसान और गरीबों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों पर अपना अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया।

इस सत्र के दौरान कुल दस विधेयक पेश किए गए। बारह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए गए और बारह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित/लौटाए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित/लौटाए गए विधेयकों की कुल संख्या भी बारह है। इस सत्र में लोकसभा की उत्पादकता दर लगभग 148 प्रतिशत और राज्यसभा की लगभग 137 प्रतिशत थी।

वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट 1 फरवरी, 2024 को पेश किया गया था। दोनों सदनों में 2024-25 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा हुई।

लोकसभा

17वीं लोकसभा के 15वें सत्र के दौरान, जो 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम बैठक थी, सदन कुल 63 घंटे और 26 मिनट तक चला। पारंपरिक रूप से सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई, जिसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी सहित 115 सदस्यों ने भाग लिया। सदस्यों द्वारा उठाए गए 1,380 अतारांकित और 120 तारांकित प्रश्नों सहित कुल 1,500 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। सदन ने अपने समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विधायी कार्य के लिए समर्पित किया, जिसमें बारह घंटे और चौबीस मिनट सात महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की गई।

राज्यसभा

राज्यसभा का 263वां सत्र 31 जनवरी, 2024 से 10 फरवरी, 2024 के बीच आयोजित किया गया था। सत्र में नौ दिनों तक चलने वाले सार्वजनिक महत्व के 116 विषयों पर विचार-विमर्श हुआ, जिसमें कुल उत्पादकता दर 137% थी। सदस्यों द्वारा उठाए गए 960 अतारांकित और 90 तारांकित प्रश्नों सहित कुल 1,050 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। विशेष रूप से इस सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा 15 क्षेत्रीय भाषाओं में चर्चा की गई, जो संसद के बहुभाषी चरित्र को प्रदर्शित करता है।

अंतरिम बजट सत्र की मुख्य बातें

- राज्यसभा में तीन विधेयक पारित किए गए हैं, जिनमें जल निवारण और प्रदूषण नियंत्रण विधेयक, जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय विधेयक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए संविधान संशोधन विधेयक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 22 निजी सदस्य विधेयक (PMB) प्रस्तुत किए गए।
- केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का अंतरिम बजट, 2024-2025 पटल पर रखा गया। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। इनके लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट प्रस्तावित किया गया है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने के कांग्रेस के प्रयासों पर प्रकाश डाला और ब्रिटिश काल के कानूनों को निरस्त करने में उनकी विफलता की आलोचना करते हुए डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के साथ उनके व्यवहार पर सवाल उठाया। उन्होंने 'सबका साथ सबका विकास' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के सरकार द्वारा अनुकरणीय प्रबंधन पर प्रकाश डाला।
- केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस बात पर जोर दिया कि 'राम राज्य' किसी विशेष धर्म पर केंद्रित नहीं था, बल्कि एक आदर्श राज्य का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी के लिए धार्मिकता और न्याय का प्रतीक है।
- भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने विश्व की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण के रूप में राम मंदिर के अभिषेक के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग लेने और अपनी संवैधानिक भूमिका के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए सभी अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर के मुद्दे का लाभ नहीं उठाती है, उन्होंने पार्टी के उस ऐतिहासिक संघर्षों का जिक्र किया जब पार्टी के पास केवल 2 सांसद थे एवं 303 सांसदों के साथ भी उसकी प्रतिबद्धता जारी रही। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत 'राम राज्य' जैसी शासन प्रणाली स्थापित करने की आकांक्षा कर सकता है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राज्यसभा में सेवानिवृत हो रहे सदस्यों को उनके बहुमूल्य योगदानों और अनुभवों को याद करते हुए विदाई दी। विदाई कार्यक्रम में उनकी संसदीय यात्रा के महत्व और साझा किए गए सामूहिक यादों को रेखांकित किया गया।
- केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट चर्चा में 33 वक्ताओं ने योगदान दिया है। ■

सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम: नरेन्द्र मोदी

प्रभु राम का शासन हमारे संविधान निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 जनवरी को कहा कि इस साल हमारे संविधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के ये पर्व 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में भारत को और सशक्त बनाते हैं। भारत का संविधान इतने गहन मंथन के बाद बना है कि उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। इसी संविधान की मूल प्रति के तीसरे अध्याय में भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये बहुत दिलचस्प है कि तीसरे अध्याय के प्रारंभ में हमारे संविधान निर्माताओं ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चित्रों को स्थान दिया था।

'देव से देश' और 'राम से राष्ट्र'

प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 109वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा करते हुए कहा कि प्रभु राम का शासन हमारे संविधान निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था और इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने 'देव से देश' की बात की थी, 'राम से राष्ट्र' की बात की थी।

श्री मोदी ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेक लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्रीराम के चरणों में समर्पित किया। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने रामज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। मैंने देश के लोगों से आग्रह किया था कि मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक स्वच्छता का अभियान चलाया जाए। मुझे अच्छा लगा कि लाखों लोगों ने श्रद्धाभाव से जुड़कर अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की साफ़-सफाई की।

> अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेक लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्रीराम के चरणों में समर्पित किया

इस बार 26 जनवरी की परेड बहुत ही अद्भुत रही

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस बार 26 जनवरी की परेड बहुत ही अद्भुत रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा परेड में Women Power को देखकर हुई, जब कर्तव्य पथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों ने कदमताल शुरू किया, तो सभी गर्व से भर उठे। महिला बैंड का मार्च देखकर, उनका जबरदस्त तालमेल देखकर देश-विदेश में लोग झूम उठे। इस बार परेड में मार्च करने वाले 20 दस्तों में से 11 दस्ते महिलाओं के ही थे। हमने देखा कि जो झांकी निकली, उसमें भी सभी महिला कलाकार ही थीं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, उसमें भी करीब डेढ़ हज़ार बेटियों ने हिस्सा लिया था।

श्री मोदी ने कहा कि 'मन की बात' में हम ऐसे देशवासियों के प्रयासों को सामने लाते हैं, जो निःस्वार्थ भावना के साथ समाज को, देश को, सशक्त करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में तीन दिन पहले जब देश ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है, तो 'मन की बात' में ऐसे लोगों की चर्चा स्वाभाविक है। इस बार भी ऐसे अनेक देशवासियों को पद्म सम्मान दिया गया है, जिन्होंने जमीन से जुड़कर समाज में बड़े-बड़े बदलाव लाने का काम किया है। इन प्रेरणादायी लोगों की जीवन-यात्रा के बारे में जानने को लेकर देशभर में बहुत उत्सुकता दिखी है।

उन्होंने कहा कि कहते हैं हर जीवन का एक लक्ष्य होता है, हर कोई एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही जन्म लेता है। इसके लिए लोग पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। हमने देखा है कि कोई समाज सेवा के माध्यम से, कोई सेना में भर्ती होकर, कोई अगली पीढ़ी को पढ़ाकर, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन हमारे बीच ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन के अंत के बाद भी समाज जीवन के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हैं और इसके लिए उनका माध्यम होता है– अंगदान। हाल के वर्षों में देश में एक हजार से अधिक लोग ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान कर दिया। ये निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन ये निर्णय कई जिंदगियों को बचाने वाला होता है। मैं उन परिवारों की भी सराहना करूंगा, जिन्होंने अपने करीबियों की आखिरी इच्छा का सम्मान किया। ■

पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को 'भारत रत्न' से सम्मानित किया जाएगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई!

भारत के पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'भारत रत्न' से सम्मानित किया जाएगा।

भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन फरवरी को कहा, "मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और भारत रत्न से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। अपने समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक श्री लालकृष्ण आडवाणी का भारत के विकास में योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर

पर काम करने से शुरू होकर हमारे उपप्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनका संसदीय योगदान हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरा रहा है। आडवाणी जी की सार्वजनिक जीवन में दशकों पुरानी सेवा को पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिह्नित किया गया है, जिसने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किए हैं। उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले।"

लालकृष्ण आडवाणी ने 'भारत रत्न' देने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया

'भारत रत्न' सम्मान से सम्मानित किये जाने पर श्री लालकृष्ण आडवाणी ने एक प्रेस बयान जारी कर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह बेहद विनम्रता और कृतज्ञता के साथ 'भारत रत्न' स्वीकार करते हैं। इस बयान में उन्होंने कहा कि यह न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान है, जिनकी मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा करने का प्रयास किया। जब मैं 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुआ, तबसे मैंने केवल एक ही इच्छा रखी— जीवन में मुझे जो भी कार्य सौंपा जाए, उससे अपने प्यारे देश की समर्पित और निःस्वार्थ सेवा की जा सके। जिस चीज ने मेरे जीवन को प्रेरित किया है वह आदर्श वाक्य है— "इदं न मम" "यह जीवन मेरा नहीं है। मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के लिए है।"

उन्होंने आगे कहा, "आज मैं उन दो व्यक्तियों को कृतज्ञतापूर्वक याद करता हूं जिनके साथ मुझे करीब से काम करने का सम्मान मिला— पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मैं अपनी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और अन्य लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे सार्वजनिक जीवन में अपनी पूरी यात्रा के दौरान काम करने का सौभाग्य मिला। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों, विशेषकर अपनी प्रिय दिवंगत पत्नी कमला के प्रति भी अपनी गहरी भावनाएं व्यक्त करता हूं। वे मेरे जीवन में शक्ति और स्थिरता का सबसे बड़ा स्रोत रही हैं। मुझे यह सम्मान प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को मेरा हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने आगे कहा कि इस अवसर पर मेरा एक ही विचार है कि हमारा महान देश महानता और गौरव के शिखर पर प्रगति करे।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जताई खुशी

श्री लालकृष्ण आडवाणी को 'भारत रत्न' से सम्मानित करने के केंद्र सरकार के फैसले पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा बधाई देते हुए कहा, "भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी को 'भारत रत्न' से सम्मानित करने का निर्णय अत्यंत सुःखद और उत्साहवर्धक है। इस निर्णय के लिए मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और आडवाणी जी को बधाई देता हूं।"

इस घोषणा से बेहद प्रसन्न हूं: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 'एक्स' के माध्यम से श्री लालकृष्ण आडवाणी को 'भारत रत्न' पुरस्कार से सम्मानित करने के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "हमारे वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी को 'भारत रत्न' देने की घोषणा से बेहद प्रसन्नता हुई। आडवाणी जी का जीवन देश और देशवासियों की निःस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित रहा है। देश के उपप्रधानमंत्री जैसे विभिन्न संवैधानिक दायित्वों पर रहते हुए उन्होंने अपने मजबूत नेतृत्व से देश की सुरक्षा, एकता एवं अखंडता के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। आडवाणी जी को भारतीय राजनीति में प्रामाणिकता के मानक स्थापित करने वाले राजनेता के रूप में जाना जाता है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने देश, संस्कृति एवं जनता से जुड़े मुद्दों के लिए अथक संघर्ष किया। पार्टी और विचारधारा में उनके अतुलनीय योगदान को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित करने का निर्णय भी करोड़ों देशवासियों का सम्मान है।"

आडवाणी जी हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, "हम सभी के प्रेरणास्रोत और देश के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय हमारे भीतर खुशी का संचार करने वाला है। वह राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। रक्षा मंत्री ने आडवाणीजी के लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान विभिन्न भूमिकाओं में उनके देश के विकास एवं राष्ट्र निर्माण में दिये महत्वपूर्ण योगदान को अविस्मरणीय एवं प्रेरणादायक बताया। उन्होंने आगे कहा कि श्री आडवाणी ने भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उन्होंने अपनी विद्वता, संसदीय एवं प्रशासनिक क्षमताओं से देश एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। उन्हें भारत रत्न सम्मान मिलना हर भारतीय के लिए खुशी की बात है। मैं इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देता हूं और आडवाणी जी को बधाई देता हूं।" ■

भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया

इस वर्ष भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। यह दिन 26 जनवरी, 1950 को संविधान को अपनाने और हमारी संप्रभुता की प्राप्ति का प्रतीक है। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस की थीम 'विकसित भारत' और 'भारतः लोकतंत्र की मातृका' रही, जो देश की आकांक्षाओं और लोकतंत्र के पोषक के रूप में इसकी भूमिका का प्रतीक है।

इस दौरान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, इस वर्ष की परेड के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रॉन, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस पूरी परेड में हजारों महिलाएं ने भाग लिया और राष्ट्रीय शक्ति एवं अपनी जीवंतता का प्रदर्शन किया। पहली बार, परेड की शुरुआत 100 से अधिक महिला कलाकारों ने की, जिन्होंने भारतीय संगीत वाद्ययंत्र बजाया। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ■

पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह एवं वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को 'भारत रत्न' से सम्मानित करने की घोषणा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 फरवरी, 2024 को घोषणा कर बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव और श्री चौधरी चरण सिंह एवं प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक श्री एमएस स्वामीनाथन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा की। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरसिम्हा राव का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपायों का प्रतीक था, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह को भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की।

उन्होंने श्री चौधरी चरण सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था।

इनके साथ ही हरित क्रांति में अहम भूमिका के लिए मशहूर डॉ. एमएस स्वामीनाथन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. एमएस स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित की है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनीतिक दलों के नेताओं ने श्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के फैसले की सराहना की। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)............................ (2)............................

ईमेल : ....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :.................................. दिनांक :............................ बैंक : ....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

नई दिल्ली में 26 जनवरी, 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 26 जनवरी, 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रॉन का स्वागत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

संसद भवन (नई दिल्ली) में 31 जनवरी, 2024 को अंतरिम बजट सत्र 2024 से पहले मीडिया को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 29 जनवरी, 2024 को 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के दौरान छात्रों के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 30 जनवरी, 2024 को गांधी स्मृति में महात्मा गांधी की याद में आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 05 फरवरी, 2024 को धार्मिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 14 फरवरी, 2024
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह